सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सफलता की ख़ुशी मनाना अच्छा है पर, उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना !

वर्ष 01, अंक 41, नई दिल्ली

बुधवार, 26 अप्रैल 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दिल्ली परिवहन विभाग के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से वाहन मालिक परेशान, आख़िर क्यों?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में व्यवसायिक वाहन मालिक जिनके वाहनों की आयु परमिट कैटेगरी के अन्तर्गत खत्म हो जाती है पर भारत सरकार के द्वारा दी गई आयु अभी बची हुई है उनके द्वारा अपना पुराना परमिट परिवहन विभाग में जमा करवाने के बाद भी परिवहन विभाग द्वारा चालित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आज भी वाहन की आयु समाप्त दिखा रहा है। व्यवसायिक वाहनों के मालिक अपने वाहनों की फिटनेस करवाने के लिए फिटनेस शाखा और परिवहन मुख्यालय में एमएलओ एवम एसटीए शाखा के पिछले कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं पर उनकी समस्या का समाधान करने को कोई तैयार नहीं। एमएलओ (एच क्यू) एसटीए शाखा और झुलझूली फिटनेस के अधिकारी वाहन मालिक के सामने किसी को ई मेल करके बता देते हैं की दो दिन में चेक कर लेना पर दो महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

आख़िर कोन है जिम्मेदार जो वाहन की आयु सीमा शेष होने पर भी वाहन मालिक को परेशानी उत्पन कर रहा है और कैसे होगा इसका समाधान, क्या परिवहन आयुक्त दिल्ली जनता को जवाब देंगे।

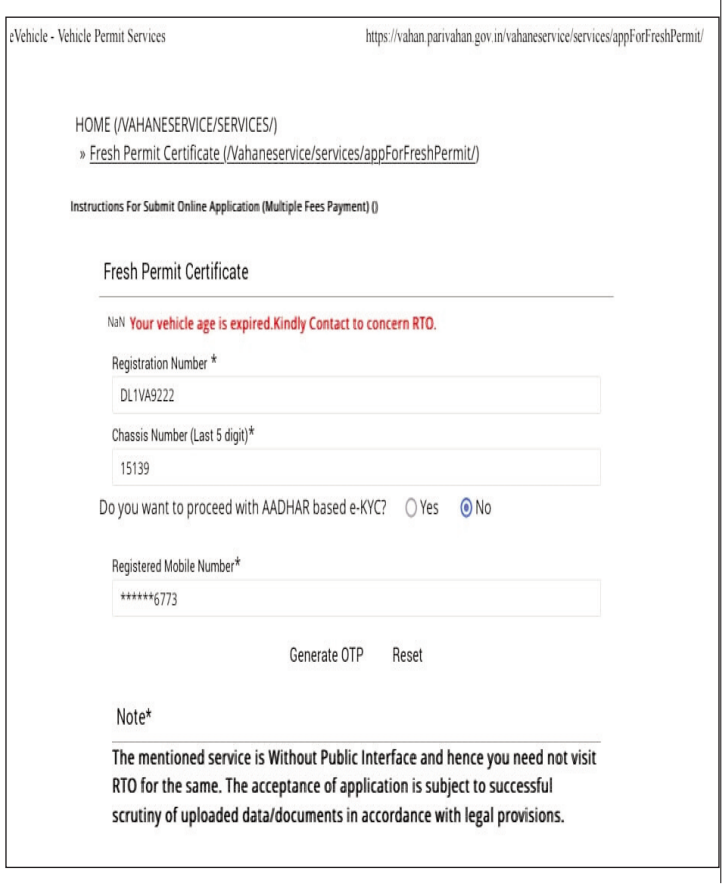

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Fornt Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/3ack will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

QR कोड से सफर कर सकेंगे मेट्रो यात्री, 50 से ज्यादा स्टेशनों पर ट्रायल शुरू

डीएमआरसी ने अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का ट्रायल शुरू कर दिया है। जल्द ही यात्री मोबाइल और क्यूआर कोड से सफर कर सकेंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में यात्री जल्द ही मोबाइल और क्यूआर कोड से सफर कर सकेंगे। इसके लिए 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये सिस्टम मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वारों पर लगाया जा रहा है। सभी स्टेशनों के एक-दो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट लगाए जा रहे हैं। जामिया नगर व लालकिला स्टेशन सहित कई स्टेशनों के गेट बदले जा चुके हैं।

सभी मेट्रो लाइनों पर एनसीएमसी की सुविधा शुरू होनी है। कुछ मेट्रो स्टेशनों पर इस सिस्टम को लगा दिया गया है। अगले साल तक यात्रियों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से यात्रियों को सफर का मौका देने के लिए एएफसी गेट अपग्रेड किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को किसी भी कार्ड से मेट्रो में सफर करने की सुविधा होगी। एएफसी गेट पर कार्ड स्वैप करते ही किराया कट जाएगा। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद निकासी के लिए भी एएफसी गेट पर कार्ड से किराये का भुगतान संभव होगा।

एयरपोर्ट लाइन पर पहले से सिस्टम

एनसीएमसी सिस्टम एयरपोर्ट लाइन पर पहले से चल रहा है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने 15 से 16 बैंकों से समझौता किया है। हालांकि, मेट्रो सूत्रों का कहना है कि एयरपोर्ट लाइन पर इस सिस्टम में कुछ जटिलताएं आ रही हैं। बैंकों को लेकर कुछ बाधाएं आ रही हैं। इस बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस लाइन पर मोबाइल पर क्यूआर स्कैन कर या प्रिंटेड क्यूआर खरीदकर यात्री सफर कर रहे हैं। इससे यात्रियों को टोकन और मेट्रो स्मार्ट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती।

नए गेट लग रहे, पुराने किए जा रहे अपग्रेड

मेट्रो के सभी स्टेशनों पर एनसीएमसी की सुविधा मुहैया करने के लिए नए एएफसी गेट लगाए जा रहे हैं। कुछ लाइनों पर पुराने गेट को ही अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि रुपे कार्ड या क्यूआर सहित किराया भुगतान के दूसरे सभी विकल्पों का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इससे यात्रियों को सफर में न तो बार बार काउंटर पर जाना होगा और न ही कार्ड को रिचार्ज करवाना होगा। इससे समय की बचत से गंतव्य तक पहुंचने की सहूलियत होगी।

यात्रियों को किराए में छूट मिलेगी

स्मार्ट कार्ड के जरिये सफर करने वालों को किराये में 10 फीसदी की छूट दी जा रही है। अवकाश के दिन कम किराया होता है। ताकि सफर में अधिक से अधिक यात्री ऑनलाइन विकल्पों को अपना सकें। मेट्रो यात्रियों को फिलहाल मेट्रो में सफर करने के लिए टोकन और स्मार्ट कार्ड का विकल्प है। एनसीएमसी लागू होने से विकल्पों में क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, क्यूआर कोड, एंड्रायड फोन भी सफर के लिए काफी होगा। इससे खासतौर पर उन यात्रियों को भी राहत मिलेगी, जिनके पास बैंक के खाते हैं, लेकिन किराया चुकाने के लिए दूसरे विकल्प का किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

पूरे नेटवर्क पर अगले साल मिलेगी सुविधा

दिल्ली गेट, लालकिला सहित दूसरे कई स्टेशनों पर नए गेट लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेशनों पर गेट को अपग्रेड किए जा रहे हैं, ताकि एनसीएमसी का इस्तेमाल किया जा सके। ब्लू लाइन के स्टेशनों पर एक-दो गेट में हार्डवेयर अपग्रेड किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को मेट्रो में क्यूआर कोड से भी सफर का मौका मिलने लगेगा। शुरुआत में चुंनिदा एक-दो एएफसी गेट पर यह सुविधा मिलेगी। अगले साल तक दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क पर एनसीएमसी का यात्रियों को फायदा मिलने लगेगा।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इस राज्य के कारण अटक गया बुलेट ट्रेन का काम, अभी पूरा होने के लिए करना होगा इतना इंतजार

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (एमएएचएसआर) या बुलेट ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग 1 लाख 8,000 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट का अगस्त 2026 तक सूरत-बिलिमोरा (63 किमी) के बीच ट्रायल रन के लिए लक्षित किया गया है...

नई दिल्ली। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। 31 मार्च तक इस प्रोजेक्ट में महज 30.15 फीसदी काम हुआ है। जानकारी के अनुसार, गुजरात की ओर 35.23 फीसदी काम हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र की ओर तस्वीर निराशाजनक है। अभी मात्र 19.65 फीसदी काम हुआ है। परियोजना पर लगभग 56.34 फीसदी सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है। अब तक 272.89 किमी का काम किया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि 170.56 किमी पर घाट का काम किया गया है, लेकिन अब तक 45.40 किमी गर्डर्स लॉन्च किए गए हैं।

भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (एमएएचएसआर) या बुलेट ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग 1 लाख 8,000 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट का अगस्त 2026 तक सूरत-बिलिमोरा (63 किमी) के बीच ट्रायल रन के लिए लक्षित किया गया है। पूरे 508 किमी लंबे मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर में महाराष्ट्र में 156 किमी और गुजरात में 352 किमी शामिल हैं। इसके 2027 तक पूरी तरह चालू होने की संभावना है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार (एनएचएसआरसीएल), बुलेट ट्रेन 320

किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी और मुंबई-अहमदाबाद के बीच की पूरी दूरी को केवल 127 मिनट में तय करेगी। एमएएचएसआर में वायडक्ट्स (460 किमी) और पुल (9.22 किमी), सुरंग (25.87 किमी), तटबंधों/कटिंग (12.9 किमी) के माध्यम से 92 फीसदी हाई-स्पीड एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल हैं।

उत्तर की ओर मुंबई-ठाणे के बीच पर्यावरण-संवेदनशील ठाणे क्रीक से गुजरने वाला रेल गलियारा एक प्रमुख आकर्षण होगा। इसमें ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य (टीसीएफएस) शामिल है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। टीसीएफएस स्थान पर राजहंस और आसपास के समृद्ध मैंग्रोव में अन्य वन्यजीवों को परेशानी से बचाने के लिए, एमएएचएसआर कॉरिडोर इस क्षेत्र में एक अंडरसीट सुरंग से गुजरेगा। यह 13.2 मीटर व्यास की एक ट्यूब के साथ भारत की पहली अंडरसीट सुरंग और देश का सबसे लंबा रेल परिवहन मार्ग होगा।

वॉटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है।

देश की पहली वॉटर मेट्रो का PM मोदी ने किया लोकार्पण, क्या कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी....

पीएम मोदी ने वॉटर मेट्रो की कल तस्वीरें जारी की थीं। उन्होंने बताया कि कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगी। इस परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली 'वॉटर मेट्रो रेल सेवा' का लोकार्पण किया। ये सेवा ऐसे शहरों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है, जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई बाधाएं हैं। आइए जानते हैं कि वॉटर मेट्रो रेल सेवा से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां-

कोच्चि वॉटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगी। करीब 1,136 करोड़ रुपये की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन व पर्यटन के जरिये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेगा।

वॉटर मेट्रो कोच्चि व आस-पास के दस द्वीपों के बीच शुरू हो रही है। पहले चरण में कोच्चि वॉटर मेट्रो हाई कोर्ट-वाइपिन टर्मिनल और विट्टिला-कक्कनाड टर्मिनल के बीच शुरू होगी

वॉटर मेट्रो पर सफर के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपये है, जो लोग नियमित यात्री होंगे वह बस या लोकल ट्रेन की तरह साप्ताहिक और मासिक पास भी ले सकते हैं। बता दें, साप्ताहिक किराया 180 रुपये, जबकि मासिक 600 रुपये वहीं, त्रैमासिक किराया 1,500 रुपये होगा। इतना ही नहीं यात्री कोच्चि मेट्रो ट्रेन और वॉटर मेट्रो में एक ही स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सफर कर सकेंगे। टिकट बुक करने के लिए आप कोच्चि वन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

वॉटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट को केरल की सरकार ने जर्मनी की KFW के साथ मिलकर फंड किया है। करीब 1,137 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए हैं।

वॉटर मेट्रो की शुरुआत पहले 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स से होगी फिर बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी।

मेट्रो ट्रेन की तरह यह पूरी तरह वातानुकूलित होंगी और रोजाना 15 मिनट के अंतराल पर 12 घंटे तक सेवाएं देंगी। अभी शुरुआत में 23 नावें व 14 टर्मिनल हैं। वहीं, प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं।

अब शहर की जरूरत के अनुसार परिवहन प्रणाली

मेट्रो लाइट : गोरखपुर, जम्मू में

अनुभव, आराम, सुविधाएं, समयबद्धता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पारंपरिक मेट्रो की तरह।

जम्मू, श्रीनगर, गोरखपुर जैसे टियर-2 व छोटे शहरों के लिए।

एक समय में अधिकतम 15 हजार लोगों को सेवाएं।

40% कम लागत पारंपरिक मेट्रो से।

मेट्रो नियो : नासिक में

रबर के पहियों वाली यह मेट्रो सेवा ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन से बिजली लेकर रोड स्लैब पर चलाई जाएंगी। पारंपरिक मेट्रो जैसी सुविधाएं।

नासिक में तैयारी। इलेक्ट्रिक बस ट्रॉली की तरह होगी।

एक समय में अधिकतम आठ हजार यात्रियों को ले जाएगी।

स्थानीय तीव्र परिवहन प्रणाली : एनसीआर, मेरठ में

देश में पहली बार स्थानीय स्तर पर तीव्र परिवहन प्रणाली या आरआरटीएस के जरिये दो शहरों को मेट्रो से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

एनसीआर-मेरठ के लिए। स्थानीय स्तर पर विकास को तेजी की उम्मीद की जा रही है। नागरिकों को भी बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी।

इनसाइड

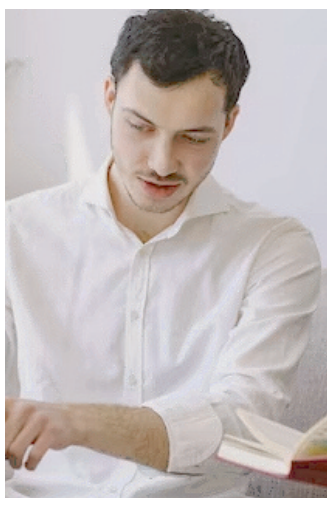

ऑफिस में महिला कलीग से बात करें तो जरूर रखें इन बातों का ख्याल, बन जाएंगे उनके फेवरेट, बॉन्डिंग भी होगी स्ट्रॉन्ग

ऑफिस में फीमेल कलीग से बात करना कई पुरुषों के लिए आसान नहीं होता है. ऐसे में पुरुष महिला कलीग के सामने भाषा पर ध्यान देने से लेकर स्माइल करने, मोटिवेट रखने जैसे कुछ टिप्स अपनाकर उनके साथ हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं.

ऑफिस में पुरुष और महिला कलीग्स दोनों मौजूद रहते हैं. ऐसे में कई मेल कलीग्स आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं मगर फीमेल कलीग्स के सामने ज्यादातर पुरुष असहज महसूस करते हैं. आप चाहें तो महिला सहकर्मी से बात करते समय कुछ चीजों का खास ख्याल रखकर ना सिर्फ उनके फेवरेट बन सकते हैं, बल्कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.

फीमेल कलीग के सामने कई सारे पुरुष नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते वे महिलाओं से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है. ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप फीमेल कलीग्स से बेस्ट बॉन्डिंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफिस में महिला कलीग से बात करने के टिप्स.

भाषा पर संयम रखें

अपने ऑफिस की किसी भी महिला कर्मचारी से बात करते समय पुरुषों को भाषा पर ध्यान देना जरूरी होता है. दरअसल, पुरुष आपस में तुम या तू करके बात करते हैं मगर महिलाओं के सामने ऐसे पेश आने से आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है. वहीं, फीमेल कलीग के सामने बॉडी लैंग्वेज भी सही रखें, जिससे वे भी आपके सामने सहज महसूस कर सकें.

स्माइल करना है जरूरी

अगर आप महिला कलीग से बात करने में असहज महसूस करते हैं तो आप उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा भी सकते हैं. फीमेल कलीग से आई कॉन्टैक्ट होने पर आपकी एक मुस्कान भी काफी है. इससे आप बिना बोले उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकेंगे और आपका रिश्ता मजबूत होने लगेगा.

काम पर ध्यान दें

महिला कलीग से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आप काम में उनकी मदद मांग सकते हैं. इससे ना सिर्फ ऑफिस का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, बल्कि काम के बीच में हंसी-मजाक करने से आपका रिश्ता भी बेहतर होने लगेगा. लेकिन, काम के दौरान पॉजिटिविटी बरकरार रखें और साथी कलीग की बुराई करने से बचें.

मोटिवेट करें

महिला कलीग को काम के प्रति मोटिवेट रखकर आप उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं. इससे फीमेल कलीग की ऑफिस परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगेगी. साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप फीमेल कलीग के फेवरेट बन जाएंगे.

टी ब्रेक पर जाएं

ऑफिस के काम में लोगों को फीमेल कलीग से बात करने का मौका कम ही मिलता है. ऐसे में आप महिला कलीग को चाय या कॉफी का ऑफर दे सकते हैं मगर ध्यान रहे कि हर रोज महिला कलीग के साथ टी ब्रेक पर ना जाएं. इससे फीमेल कलीग के साथ आप बेस्ट प्रोफेशनल रिलेशन बना सकेंगे.

भारत के इतिहास में इन वीरांगनाओं का नाम नहीं भुलाया जा सकता

इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय-समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चली हैं। आज हम अपनी खबर में ऐसी ही महिलाओं के शौर्य और वीरता की बात करेंगे जिन्होंने क्रांतिकारी गातिविधियों में अपना योगदान निडर होके दिया और कुछ ऐसी भी वीरांगनाएँ जिन्होंने असंभव प्रयास करते हुए किसी भी युग में न भूलने वाला काम किया और अमर हो गयी।

रानी लक्ष्मीबाई (19 नवंबर - 17 जून 1858)

भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा ज़रूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ़ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं ये सोचती है कि 'वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती.' देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम (1857) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं।

ऊषा मेहता सावित्रीबाई फूले (25 मार्च 1920 - 11 अगस्त 2000)

कांग्रेस रेडियो जिसे 'सीक्रेट कांग्रेस रेडियो' के नाम से भी जाना जाता है, इसे शुरू करने वाली ऊषा मेहता ही थीं. भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान कुछ महीनों तक कांग्रेस रेडियो काफ़ी सक्रिय रहा था। इस रडियो के कारण ही उन्हें पुणे की येरवाड़ा जेल में रहना पड़ा। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थीं।

बेगम हज़रत महल (1820 - 7 अप्रैल 1879)

जंगे-आज़ादी के सभी अहम केंद्रों में अवध सबसे ज़्यादा वक्त तक आज़ाद रहा। इस बीच बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में नए सिरे से शासन संभाला और बगावत की कयादत की। तकरीबन पूरा अवध उनके साथ रहा और तमाम दूसरे ताल्लुकेदारों ने भी उनका साथ दिया। बेगम हजरत महल की हिम्मत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मटियाबुर्ज में जंगे-आज़ादी के दौरान नज़रबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लार्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में भी सेंध लगा दी थी।

ऐनी बेसेंट (1 अक्टूबर 1857 - 20 सितम्बर 1933)

थियोसोफिकल सोसाइटी और भारतीय होम रूल आंदोलन में अपनी विशिष्ट भागीदारी निभाने वाली ऐनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर, 1847 को तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के लंदन शहर में हुआ था। 1890 में ऐनी बेसेंट हेलेना ब्लावत्सकी द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी, जो हिंदू धर्म और उसके आदर्शों का प्रचार-प्रसार करती हैं, की सदस्या बन गईं. भारत आने के बाद भी ऐनी बेसेंट महिला अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। महिलाओं को वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए ऐनी बेसेंट लागातार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रहीं। भारत में रहते हुए ऐनी बेसेंट ने स्वराज के लिए चल रहे होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मैडम भीकाजी कामा (24 सितम्बर 1861 - 13 अगस्त 1936)

मैडम भीकाजी कामा ने आज़ादी की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनका नाम इतिहास के पन्नोंज पर दर्ज है। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वो बाद में लंदन चली गईं और उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं मिली।

कस्तूरबा गांधी (11 अप्रैल 1869 - 22 फरवरी 1942)

मोहनदास करमचंद गांधी ने 'बा' के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधीजी से भी उन्न त थे।वह एक दृढ़ आत्म शक्ति वाली महिला थीं और गांधीजी की प्रेरणा भी। उन्होंने लोगों को शिक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी सबक सिखाए और आज़ादी की लड़ाई में पर्दे के पीछे रह कर सराहनिय कार्य किया है।

सरोजिनी नायडू (13 फरवरी 1879 - 2 मार्च 1949)

भारत कोकिला सरोजिनी नायडू सिर्फ़ स्वएतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी कवियत्री भी थीं। गोपाल कृष्ण गोखले से एक ऐतिहासिक मुलाक़ात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सरोजिनी नायडू ने खिलाफ़त आंदोलन की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया।

कमला नेहरू (1 अगस्त 1899 - 28 फरवरी 1936)

कमला विवाह के बाद जब इलाहाबाद आईं तो एक सामान्यप, कम उम्र की नई नवेली दुल्हन भर थीं. लेकिन समय आने पर यही शांत स्वाभाव की महिला लौह स्त्रीव साबित हुई, जो धरने-जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। नेहरू के साथ-साथ कमला नेहरू और फ़िर इंदिरा की प्रेरणाओं में देश की आज़ादी ही सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़-चढ़कर शिरकत की थी।

अरूणा आसफ़ अली (16 जुलाई 1909 - 26 जुलाई 1996)

अरूणा आसफ़ अली को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने एक कार्यकर्ता होने के नाते नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, साथ ही वे 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की एक सक्रिय सदस्य थीं।

विजयलक्ष्मी पंडित (18 अगस्त 1900 - 1 दिसम्बर 1990)

एक संपन्नय, कुलीन घराने से ताल्लुहक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मीं पंडित भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थीं. सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। वे संयुक्तम राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थीं जिन्होंने मास्को, लंदन और वॉशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

लूज हो रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस? महिलाएं इन 7 टिप्स की लें मदद, दमदार बन जाएगी पर्सनैलिटी

जिंदगी में सफल और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी होता है. हालांकि कुछ लोगों में कॉन्फीडेंस का लेवल अक्सर कम रहता है. ऐसे में ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने से लेकर खुद पर विश्वास रखने और आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनकर उभर सकते हैं.

शानदार पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस हाई होना बेहद जरूरी होता है. खासकर करियर को बेहतर बनाने में आत्मविश्वास का अहम योगदान होता है. हालांकि कुछ लोगों में अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस (Self confidence) की कमी देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है. तो आप कुछ आसान टिप्स की मदद ले सकते हैं. जिससे आपका आत्मविश्वास मिनटों में बढ़ता दिखाई देने लगेगा.

सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करता है. ऐसे में आत्मविश्वास को ज्यादातर लोगों का हैप्पीनेस सीक्रेट भी माना जाता है. वहीं कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण लोगों को लाइफ में काफी सफर करना पड़ सकता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के कुछ आसान टिप्स, जिसकी मदद से आप खुशमिजाज और बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर उभर सकते हैं.

ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करें

ड्रेसिंग सेंस आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है. ऐसे में अच्छी ड्रेस, मैचिंग फुटवियर और गुड लुक कैरी करके आप अंदर से काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं.

कम्युनिकेशन पर ध्यान दें

कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. ऐसे में अलग-अलग लोगों से बातचीत के दौरान अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करें. इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे.

खुद पर विश्वास रखें

खुद पर भरोसा ना होने पर लोग अक्सर कन्फ्यूज और डल महसूस करते हैं. ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना जरूरी होता है. इसलिए दूसरों की बातों पर गौर करने की बजाए अपने फैसलों का सम्मान करें.

गलतियों से ना डरें

गलतियों के डर से लोग अक्सर कुछ नया करना अवॉइड कर देते हैं. जिससे आपका अत्मविश्वास कम हो सकता है. ऐसे में आलोचनाओं का डट कर सामना करें और हमेशा नया सीखने के प्रति तत्पर रहें. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा.

दूसरों से अलग बनें

कई बार दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में लोग अपनी यूनीक पर्सनैलिटी से समझौता कर लेते हैं. हालांकि खुद को दूसरों से अलग बनाकर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं. इसलिए किसी को कॉपी करने की बजाए अपनी स्किल्स को निखारने पर फोकस करें.

डर से लड़ें

कई बार हार या आलोचनाओं के डर से लोग अपने दिल की नहीं सुनते हैं. जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुट कर रह जाते हैं. इसलिए डर से भागने की बजाए इसका डट कर सामना करें और अपनी बात रखने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं. इससे आपका कॉन्फिडेंस आसानी से बूस्ट होने लगेगा.

लोगों की बातों को करें नजरअंदाज

कुछ लोग दूसरों की बातों को अक्सर दिल से लगा लेते हैं. जिससे आप खुद अपनी सफलता में बाधक बन जाते हैं. इसलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें और खुद अपनी गलतियों से सीख लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें. इससे आप कॉन्फीडेंट और बोल्ड पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे.

50 के बाद भी रहना है हेल्दी, 4 विटामिन्स को करें डाइट में शामिल, कम दिखने लगेगी उम्र, हमेशा रहेंगी फिट

पचास की उम्र के बाद महिलाओं में कमजोरी आने लगती है. ऐसे में महिलाएं अपनी बढ़ती उम्र को कम दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं. वहीं, तमाम नुस्खे आजमाने के बाद भी महिलाएं अपनी ऐज को छुपाने में नाकाम हो जाती हैं. अगर आप 50 की हो रही हैं तो कुछ जरूरी विटामिन्स को डाइट (Diet tips) में एड करके आप उम्र के असर को आसानी से हाइड कर सकती हैं.

50 प्लस वुमेंस में विटामिन की कमी होना काफी आम बात है. ऐसे में विटामिन रिच डाइट को अवॉयड करने से ना सिर्फ महिलाएं फिजिकली वीक महसूस करने लगती हैं, बल्कि आपकी उम्र भी ज्यादा दिखती है. मेडिकलन्यूज़टुडे के मुताबिक, हम आपको बताते हैं 5 एसेंशियल विटामिन सप्लीमेंट्स के नाम, जिनका सेवन करके आप 50 के बाद भी खुद को यंग रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 को एनर्जी का बेस्ट सोर्स माना जाता है. मगर बढ़ती उम्र के साथ शरीर में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलने लगती है. ऐसे में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, अंडा, मीट और खमीर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करके आप विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

कैल्शियम रिच डाइट हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है. साथ ही कैल्शियम से भरपूर चीजें खाने से महिलाओं में फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है. ऐसे में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, बीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, बीन्स, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन और टोफू का सेवन कर सकती हैं.

विटामिन डी

50 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए विटामिन डी का सेवन भी जरूरी होता है. विटामिन डी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थकान को दूर रखने में सहायक होता है. वहीं डेयरी प्रोडक्ट, अंडा और फिश को विटामिन डी का बेहतर स्रोत माना जाता है. इसके अलावा बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप कुछ देर धूप में भी बैठ सकती हैं.

विटामिन बी 6

50 के बाद शरीर में विटामिन बी 6 की कमी होने लगती है. ऐसे में फिट और हेल्दी रहने के लिए विटामिन बी 6 से भरपूर आहार लेना जरूरी हो जाता है. वहीं गाजर, पालक, केला, दूध, चिकन और कलोंजी को विटामिन बी 6 का बेस्ट सोर्स माना जाता है.

सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक

मुख्यमंत्री के घर के पास उड़ता दिखा ड्रोन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। पुलिस जांच में जुट गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच में जुट गई है।

जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने बताया कि जानकारी मिली है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के पास एक ड्रोन देखा गया है। पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है। खास बात है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सीएम की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है।

पहले भी सुरक्षा में चूक हुई

पिछले साल सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ था। कश्मीरी हिंदुओं का अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था। साथ ही आवास के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए गेट तक पहुंच गए थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नारंगी पेट से दीवार को पेंट करने की कोशिश भी की थी। सीएम आवास पर हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी कड़ा आलोचना की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस समय कहा कि मेरे घर पर हमला हुआ। तोड़फोड़ की गई। इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना?' उन्होंने कहा था कि देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। देश महत्वपूर्ण है।

केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ की समीक्षा बैठक, जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने का दिया आदेश

मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली की जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने का अदेश दिया है साथ ही उन्होंने गंदे पानी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक में केजरीवाल ने अधिकारियों को दिल्ली की जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जल बोर्ड के साथ इस बैठक के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल ने बैठक की तस्वीरें साझा कर दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि आज दिल्ली जल बोर्ड के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया और कहा कि पानी की उपलब्धता में कराने में किसी भी तरह की ढिलाई और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गंदे पानी की शिकायत पर होगी कार्रवाई

सीएम कार्यालय ने अन्य ट्वीट में बताया कि गंदे पानी शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए एवं वहां उस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। WTP एवं प्राइमरी UGR पर खराब हुए फ्लो-मीटर्स को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए ताकि पानी की उपलब्धता और सप्लाई की जानकारी सरकार के पास हो।

450 से ज्यादा जगहों पर लगे हैं RO सिस्टम: CM

दिल्ली में कुल 450 से ज्यादा जगहों को RO सिस्टम लगाने के लिए चिन्हित किया गया था, इस काम में ढिलाई देखी जा रही है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और सख्त निर्देश दिए कि इस काम को पूरी गंभीरता से और जल्द से जल्द किया जाए।

दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं बचेंगे ड्रग तस्कर, कस्टम विभाग की K9 डॉग स्क्वॉड हुआ और मजबूत; ग्रुप में जुड़ी 'जेंसी'

राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI Airport) पर कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी की जांच के लिए डॉग यूनिट K9 को मजबूत करने के लिए एक फीमेल लैब्राडोर को जोड़ा है। जिसने हाल ही में एक नागरिक को ड्रग्स के साथ पकड़ा है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी की जांच के लिए डॉग यूनिट K9 को मजबूत करने के लिए एक फीमेल लैब्राडोर को जोड़ा है। हाल ही में इस फीमेल डॉग ने केन्या से आ रहे एक भारतीय यात्री के पास ड्रग्स बरामद करने में कस्टम अधिकारियों की मदद की।

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फीमेल लैब्रोडोर जिसका नाम जेंसी (उम्र दो साल) है, शनिवार को अचानक दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास रुक गई। उसने अधिकारियों को बैग में संदिग्ध वस्तु होने का संकेत दे दिया।

हेरोइन बरामद करने में की मदद

अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर आते ही वह तुरंत काम में जुट गई और एक यात्री के सामान पर पंजा मार दिया। इस दौरान अधिकारियों ने नैरोबी से आए भारतीय नागरिक से बैग की तलाशी लेने के लिए अनुरोध किया। अच्छे से तलाशी के लिए उसे अलग होने को कहा, फिर तलाशी में उसके पास से कथित तौर पर 3 किलो हेरोइन जब्त की। इसकी कीमत 21 करोड़ रुपये थी।

> **अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर आते ही वह तुरंत काम में जुट गई और एक यात्री के सामान पर पंजा मार दिया।**

जेंसी की तरह अन्य 11 कुत्ते भी के9 (K-Nine) में डॉग स्क्वॉड में शामिल हैं, जिन्होंने कस्टम विभाग की जांच शक्ति को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, ₹200 करोड़ रुपये मूल्य की दवाओं के अलावा, उन्हें करेंसी नोट, तंबाकू, वन्यजीव, लाल चंदन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

सिसोदिया के खिलाफ CBI ने दायर की चार्जशीट, पूर्व डिप्टी CM के अलावा इन लोगों के भी नाम

दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर की है। चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

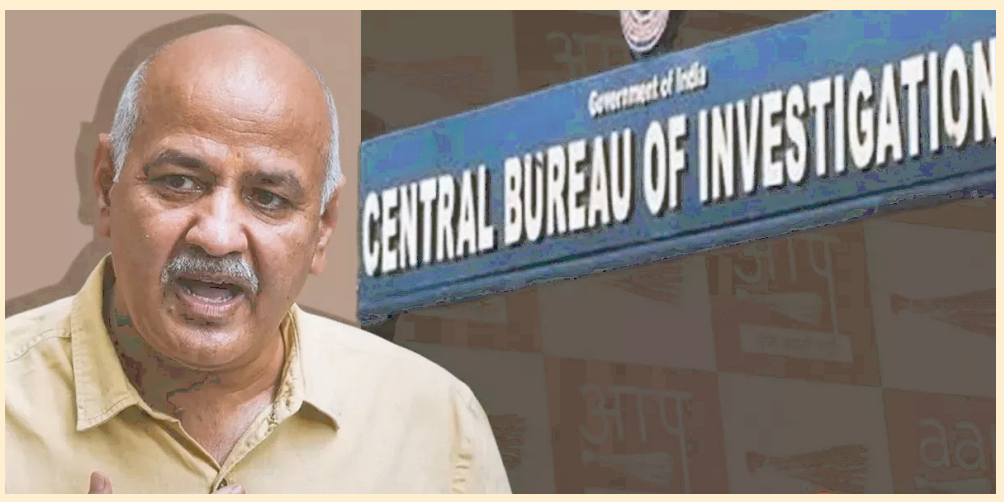

नई दिल्ली। दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दायर की है। चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई द्वारा इस मामले में दायर की गई यह दूसरी चार्जशीट है।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट के संज्ञान के बिंदुओं पर बहस के लिए 12 मई की तारीख तय की है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बूची बाबू का भी नाम है। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120बी, 201 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 और 13 के तहत आरोपियों के नाम हैं।

हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध

आबकारी नीति घोटाला मामले में 20 अप्रैल को दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं और अपराध के तौर-तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दाखिल लिखित संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने कहा कि जांच की प्रगति को विफल करने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने का यह प्रयास है।

सिसोदिया षडयंत्र के सरगना हैं- CBI

सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया षड्यंत्र के सरगना हैं और उनका प्रभाव और दबदबा है। ऐसे में जमानत पाने वाले सह-आरोपितों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सुबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

जेल में बंद मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी को मंगलवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक सूत्र ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं। उनकी हालत बिगड़ गई थी और इंद्रप्रस्थ अपोले अस्पताल में भर्ती कराया है। आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy 20221-22) में फरवरी में आप नेता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान सिसोदिया के आवास पर उनकी पत्नी से मिलने पहुंचे थे और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि सीमा सिसोदिया ₹एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। केजरीवाल ने कहा था, ₹यह मल्टीपल स्केलेरोसिस है, जिसमें दिमाग धीरे-धीरे शरीर पर नियंत्रण खो देता है। वह घर पर अकेली हैं। मनीष उनकी देखभाल करते थे।₹ उन्होंने कहा था कि सिसोदिया के बेटे पढ़ाई के लिए विदेश में हैं।

ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान WFI के प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

आखिर जंतर-मंतर पर ही प्रदर्शन क्यों? जानिए कैसे एक ऐतिहासिक धरोहर बनी लोकतंत्र की आवाज

दिल्ली में जंतर-मंतर के प्रदर्शन स्थल बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। जंतर-मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन साल 1993 में हुआ था। इसके बाद यह अन्ना हजारे से लेकर मेधा पाटकर जैसे समाजसेवियों के प्रदर्शन का गवाह रहा है जिन्होंने देश की सत्ता की जड़े हिलाकर रख दी थीं।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के दिल में स्थित जंतर-मंतर वैसे तो अपनी खूबसूरती और आस-पास मौजूद हरियाली के लिए पर्यटन का केंद्र बना रहता है लेकिन यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की भी मिसाल है। हालांकि आज की पीढ़ी के बीच जंतर-मंतर की पहचान यहां होने वाले दर्जनों प्रदर्शनों के कारण है। जंतर-मंतर कई ऐसे प्रदर्शनों का साक्षी रहा है जिसने देश की सत्ता और शासन को झुकने पर मजबूर किया। पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग जंतर-मंतर को अपने प्रदर्शन के लिए क्यों चुनते हैं, कैसे एक ऐतिहासिक धरोहर लोकतंत्र की आवाज बनी, अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों के इतिहास के बारे में...।

पहलवानों का प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान WFI के प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई और अन्य कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

वहीं, पहलवानों की अर्जी पर मंगलवार 25 अप्रैल को सुप्रीम ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और पुलिस से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 28 अप्रैल को होगी। इससे पहले पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ जनवरी में प्रदर्शन किया था। तब सरकार के आश्वासन पर उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर फिर से विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं।

कब हुआ जंतर-मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन

जंतर-मंतर की देश के सबसे बड़े प्रदर्शन स्थल के रूप में उभरने की कहानी बेहद रोचक है। संसद भवन के करीब होने की वजह से यहां हर वक्त विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहते हैं, जबकि कुछ लोग तो वहां सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन 1993 में DUSU के अध्यक्ष आशीष सूद ने केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद किया था। इसके बाद से यह हजारों छोटे-बड़े प्रदर्शनों का गवाह बन चुका है।

अन्ना हजारे आंदोलन

अपने प्रदर्शन से देश की सत्ता की जड़ें हिला देने वाले अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन की शुरुआत अप्रैल, 2011 में यहीं से की थी। महाराष्ट्र के समाजसेवी हजारे ने लोकपाल बिल लाने और देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यहीं से आंदोलन शुरू किया था और इसके बाद जो हुआ उसका गवाह पूरा देश है। अन्ना हजारे के इस आंदोलन से देश को कई नेता मिले तो इस आंदोलन से कई नए समाजसेवियों का भी जन्म हुआ।

समाज सेवी मेधा पाटकर के नेतृत्व में साल 2013 में नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके बाद साल 2017 में तमिलनाडु के किसानों ने सूखा राहत पैकेज देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से राहत के लिए भारी भरकम रकम की मांग की थी।

एनजीटी ने प्रदर्शनों पर लगाई रोक

एनजीटी ने साल 2017 में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। एनजीटी ने कहा था कि इन प्रदर्शनों की वजह से इस जगह की हरियाली खराब हो रही है और इलाके में गंदगी भी फैल रही है। साथ ही एनजीटी ने लोगों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की सलाह दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने 2018 में एनजीटी के इस आदेश पर रोक लगाते हुए दिल्ली पुलिस से नई गाइडलाइन जारी करने को कहा था।

जंतर-मंतर से पहले यहां होते थे विरोध प्रदर्शन

बताया जाता है कि किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ के विरोध ने अक्टूबर, 1988 में सरकार को हिला दिया था। उस दौर में राजधानी ने कई सालों बाद उस वक्त का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा था। टिकैत हजारों आंदोलनकारी किसानों और मवेशियों के साथ प्रदर्शन के लिए दिल्ली के बोट क्लब पहुंचे थे। मवेशियों के बोट क्लब के पास पहुंचने से यह पूरा इलाका बुरी तरह गंदगी से भर गया। इसके बाद सरकार ने एक कानून लाकर बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए आधिकारिक स्थल बना दिया। वहीं, बोट क्लब से पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन अकबर रोड पर हुआ करते थे।

कब हुआ जंतर-मंतर का निर्माण

आज भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना चुका जंतर-मंतर हजारों विरोध प्रदर्शनों का गवाह है। दिल्ली के बीचों-बीच स्थित जंतर-मंतर का निर्माण साल 1724 में महाराज जयसिंह द्वितीय ने कराया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है। मोहम्मद शाह के शासन काल में हिन्दू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी, जिसको खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर-मंतर का निर्माण करवाया। उन्होंने दिल्ली के साथ-साथ जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण कराया था। बताया जाता है कि दिल्ली का जंतर-मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है।

गाजियाबाद में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, आराध्य और अमान बने जिला टॉपर

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2022-23 की बोर्ड परीक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं में आराध्य अग्रवाल ने और 12वीं में महर्षि दयानंद विद्यापीठ के अमान सैफी ने 95.60 प्रतिशत अंक पाकर जिला टॉप किया।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2022-23 की बोर्ड परीक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं में मोदीनगर के डॉ. केएन मोदी साइंस एंड कामर्स कॉलेज के आराध्य अग्रवाल ने 94.80 प्रतिशत अंक और 12वीं में महर्षि दयानंद विद्यापीठ के अमान सैफी ने 95.60 प्रतिशत अंक पाकर जिला टॉप किया।

जिले में इस बार हाईस्कूल में 28,428 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 26,953 छात्रों ने परीक्षा दी और इंटरमीडिएट में पंजीकृत 24,182 में से 22,740 छात्रों ने परीक्षा दी थी। सफल होने वाले विद्यार्थियों की कंपाइल रिपोर्ट कुछ देर में जारी होगी। जिले में 10वीं कक्षा की दूसरी जिला टॉपर ज्योति मिश्रा हैं, जो कैलाशवती इंटर कॉलेज का छात्रा हैं। इन्होंने 600 में से 567 (94.50%) अंक हासिल किए हैं।

यूपी में गिरा रिजल्ट

यूपी बोर्ड इंटर के रिजल्ट में इस साल गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष के नतीजे कम बेहतर रहे हैं। साल 2023 में, जहां कुल 75.52 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं, 2022 में यह आंकड़ा 85.33 फीसदी रहा था। इस आधार पर देखें तो करीब 9 फीसदी से ज्यादा परिणाम में गिरावट देखने को मिली है

वहीं लड़कियों का पास प्रतिशत देखें तो पिछले वर्ष 90.15 फीसदी रहा था, जबकि 81.21 फीसदी रहा था। वहीं, अगर इस साल को देखें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 2023 में लड़कियों का पास प्रतिशत 83% फीसदी रहा है। वहीं लड़कों का रिजल्ट काफी कम रहा है। यह 69.34 फीसदी पर सिमट गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं।

मैट्रिक में हुआ सुधार

यूपी बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में कुछ सुधार देखने को मिला है। पिछले साल जहां, 88.19 फीसदी स्टूडेंट्स हुए थे। वहीं, इस साल 10वीं का पास प्रतिशत 89.78 रहा है। वहीं, अभी तक जिन परीक्षार्थियों ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर के परिणाम चेक नहीं कर पाए हों वे पोर्टल पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं।

कांग्रेस की पुष्पा के पास XUV, सपा की पूनम हैं बे-कार, बसपा की निसारा पांचवीं पास

गाजियाबाद निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। सोमवार को सबसे अधिक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया जानें प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने महापौर पद के लिए जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी कितनी संपत्ति है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति के साथ ही शिक्षा समेत शपथ पत्र के साथ अपना तमाम ब्यौरा भी दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के पास महेंद्रा एक्सयूवी कार है तो सपा प्रत्याशी ने उनके नाम कोई कार न होने का शपथ पत्र दिया है। शिक्षा में कांग्रेस प्रत्याशी अव्वल हैं तो संपत्ति में सपा प्रत्याशी।

सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। शपथ पत्र में पति-पत्नी दोनों की चल-अचल संपत्ति के साथ शिक्षा और जेवरात का भी ब्यौरा दिया है।

सपा उम्मीदवार पूनम यादव ने शपथ पत्र में अपनी चल-अचल संपत्ति की कीमत करीब 21 करोड़ बताई है, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल ने अपनी चल-अचल संपत्ति को पांच करोड़ से अधिक आंका है।

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा रावत की चल-अचल संपत्ति करीब ढाई करोड़ और बसपा प्रत्याशी निसारा खान की संपत्ति करीब एक करोड़ रुपये है। वहीं, वाहनों की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल आल्टो और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्रा की एक्सयूवी की सवारी करती हैं।

सपा प्रत्याशी पूनम यादव के नाम कोई कार नहीं है, लेकिन उनके पति सिकंदर यादव के पास जरूर लग्जरी गाड़ियां हैं। बसपा प्रत्याशी निसारा खान स्कूटी की मालिक हैं।

सोने की शौकीन

नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल ने अपने पास 250 ग्राम सोने के जेवर होने की बात की है। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा रावत ने 22 तोला सोना व 500 ग्राम चांदी, बसपा प्रत्याशी निसारा खान के पास 40 ग्राम सोने के जेवर और सपा प्रत्याशी पूनम यादव के पास 10 तोला सोना होने का शपथ पत्र दिया है।

बसपा की निसारा हैं पांचवीं पास

महापौर प्रत्याशियों की सूची में बसपा प्रत्याशी निसारा खान पांचवी कक्षा तक पढ़ी होने का शपथ पत्र दिया है। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा रावत एमए, भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल ग्रेजुएट और सपा प्रत्याशी पूनम यादव ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है।

चुनाव से पहले 134 शरारती तत्वों को पुलिस जारी करेगी रेडकार्ड, रह सकते हैं नजरबंद

जिले में वर्तमान में एक नगर निगम चार नगर पालिका व चार नगर पंचायत हैं। जिले में वर्तमान में कुल 294 वार्ड 606 मतदान केंद्र व 2371 मतदान बूथ हैं। इन सभी पर पुलिस ने आचार संहिता लगने से पहले ही काम शुरू कर दिया था।

गाजियाबाद। नगर निकाय चुनाव को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने 134 ऐसे लोगों को चिह्नित किया है जो शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव में रोड़ा बन सकते हैं। ये सभी लोग वर्ष 2012 व वर्ष 2017 में हुए नगर निकाय चुनाव में भी शांति-व्यवस्था में बाधक बने थे।

पिछले रिकार्ड को खंगाल कर पुलिस ने इन लोगों की कुंडली तैयार कराई है। चुनाव से पूर्व ही इस सभी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने के साथ इन शरारती तत्वों को रेड कार्ड जारी किए जाएंगे।

इन लोगों को लेकर अंदेशा जताया गया है कि ये शांतिपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और चुनाव में खलल डाल सकते हैं। ये लोग चुनाव तो प्रभावित कर ही सकते हैं साथ ही वोटरों को भी प्रभाव में ले सकते हैं।

पुलिस इनके खिलाफ पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 107/16 व गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में ला रही है। सभी को मुचलकों में पाबंद किया जा रही है।

साथ ही पुलिस व खुफिया विभाग अभी से इनकी गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है। जिले में वर्तमान में एक नगर निगम, चार नगर पालिका व चार नगर पंचायत हैं। जिले में वर्तमान में कुल 294 वार्ड, 606 मतदान केंद्र व 2371 मतदान बूथ हैं। इन सभी पर पुलिस ने आचार संहिता लगने से पहले ही काम शुरू कर दिया था।

मतदान के बाद किया जा सकता है नजर बंद

पुलिस जिन लोगों को रेड कार्ड जारी करेगी, उन्हें मतदान वाले दिन केवल मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद वह घर से नहीं निकल सकेंगे। माहौल को देखते हुए ऐसे लोगों को घरों में नजरबंद किया जा सकता है। घर पर भी इनकी गतिविधियों पर पुलिस निगाह रखेगी। इन्होंने यदि किसी भी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से पहले भी बीट कांस्टेबलों के माध्यम से इनकी नियमित निगरानी कराई जाएगी।

पुलिस द्वारा की गई चुनावी कार्रवाई

अवैध शस्त्र बरामद - 37
कारतूस बरामद किए- 49
विस्फोटक सामग्री पकड़ी- 126 किलो
अवैध शराब पकड़ी- 1821 लीटर
शराब तस्कर गिरफ्तार - 43
धारा 151 में की गई कार्रवाई - 855
धारा 107/16 में रिपोर्ट की संख्या - 1122
धारा 107/16 में निरुद्ध लोगों की संख्या - 8944
मुचलकों में पाबंद किए गए लोग - 1323
गैर जमानती वारंटियों की गिरफ्तारी - 153

गैर जमानती वारंटियों की गिरफ्तारी शेष - 230
वांछित अपराधी गिरफ्तार - 182
कोर्ट में सरेंडर करने वाले - 39
गिरफ्तारी होने से शेष - 230

वाहनों की चेकिंग के लिए बनाए गए चेकपोस्ट

कुल चेकपोस्ट - 89
चेक किए गए वाहन - 328989
चालान किए गए - 115595
सीज किए गए वाहन - 1342
आनलाइन चालान किए गए - 41016

एडीसीपी क्राइम एवं नगर निकाय चुनाव के नोडल अधिकारी, सच्चिदानंद ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को शांतिपर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शरारती तत्वों की पहचान कराई जा रही है। इन लोगों को चिह्नित कर इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और इन्हें रेड कार्ड जारी किए जाएंगे। माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी।

अब बिना आधार कार्ड के भी बन सकता है पासपोर्ट, इस डॉक्यूमेंट से भी चल जाएगा काम

गाजियाबाद के कविनगर में रहने वाले संतोष कुमार का आधार कार्ड खो गया था। दोबारा से आधार कार्ड बना नहीं था। उन्होंने बिना आधार कार्ड के ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया और उनका पासपोर्ट बन भी गया पढ़ें कैसे हुआ ये...

गाजियाबादः अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड खो गया है और आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं।

बैंक पासबुक भी करेगा काम

बैंक पासबुक के आधार पर भी पासपोर्ट बन सकता है पर उसके लिए पासबुक में पासपोर्ट आवेदक की अपडेट फोटो व लेन-देन की अपडेट एंट्री होना जरूरी है। दरअसल, अभी जो लोग पते के दस्तावेज के रूप में बैंक पासबुक पेश करते हैं। उनमें से ज्यादातर वर्तमान की एंट्री कराकर नहीं लाते हैं।

95 प्रतिशत लोग करते हैं ये गलती

अधिकतर की पासबुक पर फोटो भी नहीं लगी होती है। इसी कारण उन्हें पासपोर्ट जारी करने में देरी होती है। पते के दस्तावेज के रूप में पासबुक लेकर आने वाले 95 प्रतिशत आवेदकों के आवेदन में यह खामी होती है।

केस-एक

गाजियाबाद के कविनगर में रहने वाले संतोष कुमार का आधार कार्ड खो गया था। दोबारा से आधार कार्ड बना नहीं था। उन्होंने बिना आधार कार्ड के ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया। बायोमीट्रिक के वक्त पते के दो दस्तावेजों के रूप में उन्होंने वोटर कार्ड व बैंक पासबुक पेश की, पर पासबुक पर फोटो नहीं थी और लेन-देन की एंट्री एक साल पुरानी थी। इस पर पहली बार में उनकी फाइल होल्ड करते हुए दोबारा से पासबुक पर फोटो लगवाकर व अपडेट एंट्री के साथ आने को कहा गया। वह पासबुक नियमानुसार अपडेट कराकर पहुंचे, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट जारी हुआ।

पासपोर्ट आवेदकों की सहूलियत के लिए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट प्रक्रिया बेहद सरल कर दी है लेकिन कुछ मानक पूरे करने होते हैं जैसे बैंक पासबुक पेश करते वक्त उस पर अपडेट फोटो व अपडेट एंट्री कराकर दें। - सुब्रतो हाजरा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, गाजियाबाद

केस-दो

मेरठ के रहने वाले अंकित त्यागी नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनका आधार कार्ड नहीं बना था। इससे उनके कई कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वजन ने उनका पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया। पते के दस्तावेज के रूप में उन्होंने सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र पेश किया। दूसरा कोई दस्तावेज वह पेश नहीं कर पाए। ऐसे में उस वक्त उनकी फाइल होल्ड कर दी गई। उन्हें बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक पर अपडेट फोटो व लेन-देन की अपडेट एंट्री कराकर पेश करने के लिए कहा गया। ऐसा करने के बाद ही उनके पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया पूरी हुई।

किस वार्ड में कौन है सपा का प्रत्याशी, महानगर अध्यक्ष को खबर ही नहीं

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निकाय चुनाव में सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन रहा। सभी राजनीतिक दल ने अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की लेकिन गाजियाबाद नगर निगम में पार्षद पद पर प्रत्याशियों की सूची सपा जारी नहीं कर सकी। गाजियाबाद के सपा के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को भी यह नहीं पता कि किस वार्ड में कौन प्रत्याशी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा है। सपा ने हाल ही में वीरेंद्र यादव को महानगर अध्यक्ष और फैसल हुसैन को जिलाध्यक्ष बनाया है। जिस समय दोनों को जिले में पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त टिकट को लेकर सपा-रालोद-आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे की स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुछ वार्डों में पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर दी थी। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी के प्रदेश कार्यालय से की गई है।

प्रत्याशियों के बारे में कर रहे हैं जानकारी: महानगर अध्यक्ष

वहीं, कुछ प्रत्याशियों के नाम भी काटकर दूसरे प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। चुनाव चिह्न भी प्रदेश कार्यालय से आवंटित हुए। सपा के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का कहना है कि प्रत्याशियों के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं।

इनसाइड

महापौर की महिला सीट पर सामान्य से ज्यादा ओबीसी प्रत्याशी, रोमांचक होगा चुनाव

सियासी लड़ाई में वोटरों को साधने के लिए अब चुनाव प्रचार शुरू होगा ऐसे में देखना है कि मतदाताओं का झुकाव किस प्रत्याशी की ओर होगा। महापौर की सीट पर भाजपा ने सामान्य वर्ग से वैश्य समाज की सुनीता दयाल को प्रत्याशी बनाया है।

गाजियाबाद। नगर निकाय चुनाव में गाजियाबाद महापौर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है। इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के छह प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। सामान्य वर्ग के पांच प्रत्याशी ने नामांकन कराया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर असर पड़ सकता है। चुनाव भी रोमांचक होगा। महापौर की कुर्सी पर कब्जे के लिए दूसरे वर्ग के मतदाताओं का साथ भी प्रत्याशियों को चाहिए होगा। जातीय समीकरण के साथ ही विकास के मुद्दे भी चुनाव में अहम होंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा, जिससे कि जातीय समीकरण को साधा जा सके। सपा की सियासी चाल यह है कि ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के बीच संदेश जाए कि उन्होंने महिला सीट पर भी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को न उतार कर ओबीसी वर्ग को अधिक महत्व दिया है।

ओबीसी वोटरों की संख्या छह लाख से अधिक

रालोद और आजाद समाज पार्टी के साथ सपा का गठबंधन भी है। महापौर सीट पर कुल 15.39 लाख मतदाताओं में से ओबीसी वोटरों की संख्या छह लाख से अधिक है। ओबीसी के साथ ही सपा पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं और सामान्य वर्ग के वोटरों को साथ लेकर इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन महापौर सीट पर पांच और ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों ने दावेदारी की है। इसमें बसपा की निसारा खान, जन अधिकार पार्टी की पिंकी प्रजापति, एआइएमआइएम की शहनाज मलिक, निर्दलीय बबीता डागर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सविता यादव शामिल हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से नीरज प्रकाश चौधरी ने दावेदारी की है।

इनसाइड

हीरो स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले कितनी दमदार है होंडा शाइन 100, कौन किस मामले में बेहतर

भारतीय बाजार में हीरो और होंडा दोनों कंपनियों की बाइक्स अधिक सेल होती है। हाल के दिनों में लॉन्च की गई होंडा शाइन 100 का मुकाबला स्प्लेंडर प्लस से है। आज हम आपके लिए Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus की तुलना लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। हीरो और होंडा दोनों ही कंपनियां भारतीय बाजार में आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रही है। ये तो आपने भी खुद अनुभव किया होगा कि भारतीय सड़कों पर अधिकतर हीरो और होंडा की बाइक्स दिखाई देती है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने शाइन 100 के लॉन्च के साथ 100 सीसी मोटरसाइकिल कैटेगरी में कदम रखा है। नई 2023 होंडा शाइन 100 को भारतीय बाजार में 64,900 रुपये एक्स-शोरूम में लॉन्च किया गया है और इसका मुकाबला स्प्लेंडर प्लस से है। आज हम आपके लिए एंट्री-लेवल 100cc कम्यूटर मोटरसाइकिल की तुलना लेकर आए हैं।

Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus डिजाइन और कलर

डिजाइन के मामले में, इन दोनों मोटरसाइकिल का लुक ही लोगों को अधिक पसंद आता है। वाहन निर्माता कंपनी ने होंडा शाइन 100 को पांच कलर ऑप्शन में पेश किया है, जबकि स्प्लेंडर प्लस बारह पेंट कलर ऑप्शन में ही आती है।

Honda Shine 100 vs Hero Splendor Plus इंजन और गियरबॉक्स

Honda Shine 100 में 99.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो 7.6 bhp और 8.05 Nm का टार्क जनरेट करती है। दूसरी ओर, हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड मोटर मिलता है जो 7.9 bhp और 8.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। ये दोनों मोटरसाइकिलें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ी हैं। इसके अलावा ये 60-70 kmpl का माइलेज देती है। नई होंडा शाइन 100 के साथ-साथ हीरो स्प्लेंडर प्लस स्पोर्ट टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर में डुअल स्प्रिंग-लोडेड शॉक एब्जॉर्बर के साथ आती है। दोनों में ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दोनों ओर ड्रम ब्रेक द्वारा ब्रेकिंग ड्यूटी है।

बड़े काम की साबित हो सकती है ये छोटी-सी इलेक्ट्रिक कार, लग्जरी फीचर के साथ देगी 230 KM की रेंज

कॉमेट ईवी में 17.3 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जिसे टाइप 2 चार्जर का उपयोग करके लगभग 7 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकता है। एमजी का दावा है कि एक फुल चार्ज पर कॉमेट ईवी की रेंज करीब 230 किलोमीटर है।

नई दिल्ली। अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कार Comet EV को कल यानी बुधवार के दिन देश में आधिकारिक रूप से लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की ये दूसरी ऑल-इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले एमजी के पास एकमात्र इलेक्ट्रिक कार जेडएस ईवी के रूप में मौजूद है।

कंपनी ने MG Comet को एकदम अलग डिजाइन दी है, मुख्य रूप से युवा कार खरीदारों को लक्षित करके बनाया गया है। उम्मीद है कि कंपनी अपनी इस कार को किफायती दामों में लॉन्च करेगी। आइए इससे संबंधित सभी जानकारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

MG Comet EV की डिजाइन

एमजी की ये इलेक्ट्रिक कार दो दरवाजों और चार सीटों के साथ आती है। ये छोड़ी सी ईवी कार भीड़भाड़ वाले शहरों में काफी प्रक्टिकल साबित होने वाली है। आपको बता दें कि इसका टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है। MG Comet EV को गुजरात के हलोल में कंपनी के प्लांट में स्थानीय रूप से निर्मित किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक कार GSEV प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

MG Comet EV का डायमेंशन

इसे भारत की सबसे कॉम्पैक्ट ईवी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी लंबाई 2,974 मिमी, चौड़ाई 1,505 मिमी और ऊंचाई 1,640 मिमी है। MG Comet EV का व्हीलबेस 2,010 मिमी है। दिखने में ये क्यूट सी इलेक्ट्रिक कार नजर आती है।

MG Comet EV की बैटरी और रेंज

कॉमेट ईवी में 17.3 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जिसे टाइप 2 चार्जर का उपयोग करके लगभग 7 घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकता है। आपको जानकर निराशा हो सकती है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है। एमजी का दावा है कि एक फुल चार्ज पर कॉमेट ईवी की रेंज करीब 230 किलोमीटर है। व्यावहारिक रूप से परीक्षण होने के बाद ही इसका सही से अनुमान लगाया जा सकेगा।

MG Comet EV की मोटर और पॉवर

MG Motor India की Comet EV में सिंगल मोटर है जो इसके रियर एक्सल पर लगाया गया है। इसमें 41 hp का पीक पावर आउटपुट और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट होता है। कॉमेट ईवी की टॉप स्पीड 100 किमी प्रति घंटा है और यह तीन ड्राइव मोड्स - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट के साथ आती है।

MG Comet EV के वेरिएंट और रंग विकल्प

कंपनी इसे 2 वेरिएंट और तीन सिंगल-टोन और दो डुअल टोन रंग विकल्पों के साथ पेश करती है। सिंगल-टोन रंग विकल्पों में ब्लैक, सिल्वर और व्हाइट वहीं डुअल-टोन में ब्लैक रूफ के साथ व्हाइट और ब्लैक रूफ के साथ ग्रीन का विकल्प मिलता है।

क्या होता है कारों में A-B-C-D और J सेगमेंट, आसान भाषा में समझिए इनका अंतर

कार निर्माता कंपनी अपने वाहनों को अलग-अलग सेग्मेंट में वर्गीकृत करके बेचती हैं। इनमें ABCD और J सेग्मेंट शामिल हैं। हम आपको इन सभी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। कार के सेगमेंट को लेकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए।

नई दिल्ली। सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कारों के आकार और डायमेंशन के हिसाब से इन्हें A,B,C,D और J सेगमेंट में वर्गीकृत करती हैं। क्या आपको इन सभी टर्म के बारे में पता है? अगर जवाब है नहीं, तो आप इस लेख को पढ़ने के बाद कारों के इन सभी सेगमेंट के बारे में जान जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप जिस कार के मालिक हैं, वो किस श्रेणी में आती है।

आकार और डायमेंशन के हिसाब से होता है वर्गीकरण

कंपनी जब किसी कार को डिजाइन करती है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि इसे किन ग्राहकों के लिए बनाया जाय और इसका आकार और डायमेंशन क्या होना चाहिए। इसलिए ही कारों को A,B,C,D और J सेगमेंट में बांटा गया है। आपको बता दें कि सबसे छोटी कारों को A, वहीं सबसे बड़े आकार की गाड़ियों को J सेगमेंट में शामिल किया जाता है। आइए, आपको अब A से लेकर J सेगमेंट को आसान भाषा में समझाते हैं।

A-सेगमेंट

ये गाड़ियां आकार में छोटी होती हैं और शहरी रास्तों के लिए ठीक होती हैं। इन्हें अच्छी सड़कों पर आसानी से चलाया जा सकता है। A-सेगमेंट की गाड़ियों का इंजन और वजन भी हल्का रखा जाता है। इन्हें एंट्री लेवल मॉडल और कॉम्पैक्ट हैचबैक भी कहा जाता है।

B-सेगमेंट

इस सेगमेंट की कारों को स्मॉल हैचबैक और प्रीमियम हैचबैक के नाम से जाना जाता है। A-सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले ये ज्यादा ऊंची और चौड़ी होती हैं। B-सेगमेंट की कार में 4 लोग आसानी से बैठ जाते हैं।

C-सेगमेंट

इस सेगमेंट की कार की लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन ये कम ऊंची होती है। A और B सेगमेंट के मुकाबले इसमें बैठने के लिए ज्यादा जगह होती है, कारण है कार की ज्यादा लंबाई। C-सेगमेंट की कारों को सेडान के नाम से भी जाना जाता है।

D-सेगमेंट

इस सेगमेंट में मिड साइज फैमली कार और Sedan को शामिल किया जाता है। ये C-सेगमेंट वाली कार के मुकाबले ज्यादा बड़ी और पॉवरफुल होती हैं। श्रेणी में प्रीमियम सेडान कार भी आती हैं।

J-सेगमेंट

Cars की इस श्रेणी को मौजूदा समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इन कारों को SUV यानी Sports utility vehicle कहा जाता है। ये कारें सभी रास्तों पर चलने में सक्षम होती हैं। इनको भी आकार और डायमेंशन के मुताबिक B, C और D श्रेणी में विभाजित किया जाता है।

MPV-सेगमेंट

ये बहुउद्देशीय कार होती हैं। इसी वजह से इन्हे MPV यानी Multi Purpose Vehicle कहा जाता है। बड़े परिवार के लिए ये कार सुविधाजनक रहती है। इन कारों की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ठीक-ठाक होती है।

सेकेंड हैंड कार खरीदते समय इन 5 चीजों का जरूर रखें ख्याल, मिलेगी बेहतरीन डील

सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं उसके मौजूदा इंश्योरेंस पेपर हैं या नहीं। पेपर के साथ यह भी जांच लें कि कार से कोई दुर्घटना या क्लेम तो नहीं किया गया है।

नई दिल्ली। लोग अक्सर सेकेंड हैंड कार खरीदते समय ठग जाते हैं। इसका मुख्य कार गाड़ी संबंधित कम जानकारी होना है। इसलिए अगर आप भी यूज्ड कार खरीदने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें, जहां आपको 5 टिप्स बताएं गए हैं। इनकी मदद से आप अच्छी डील कर सकते हैं।

गाड़ी की कंडीशन चेक करें

अपनी जरूरतों के आधार पर एक सही कार खोजने के बाद कार की स्थिति की जांच करना पहला और महत्वपूर्ण कदम है। कार स्थिति (कंडीशन) का मतलब है कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रेमिंग, टायर, इंजन, माइलेज, ओडोमीटर, टेस्ट ड्राइव और इंजन सहित बहुत सी चीजें हैं जिन्हें चेक करना काफी जरूरी है, ताकि आप कार के हेल्ड की जांच कर सकें। इन पैरामीटर को चेक करने के बाद ही आपको सही कीमत तय कर पाएंगे।

सर्विस हिस्ट्री चेक करें

बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी खरीदने की इतनी जल्दी रहती हैं कि लोग सर्विस हिस्ट्री के बारे में पूछना भूल जाते हैं। आप अगर सेकेंड हैंड कार देखने जा रहे हैं तो संबंधित सर्विस हिस्ट्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें।

इंश्योरेंस पेपर चेक करें

सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं, उसके मौजूदा इंश्योरेंस पेपर हैं या नहीं। पेपर के साथ यह भी जांच लें कि कार से कोई दुर्घटना या क्लेम तो नहीं किया गया है। जानकारी के लिए बता दें, वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी पर इसे देखने का तरीका यह है कि लागू किए गए नो क्लेम बोनस (NCB) प्रतिशत पर ध्यान दें।

टेस्ट ड्राइव जरूर लें

वाहन को खरीदनें से पहले उसके ब्रेक की जाँच करें। कार को ऐसी जगह कम से कम 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं जिसमें ट्रैफिक कम हो। ब्रेक पैडल से किसी भी कंपन या किसी भी अजीब आवाज का एहसास हो तो तुरंत मैकेनिक से परामर्श लें।

2023 Kia Sonet, Seltos और Carens को किया गया अपडेट, कीमत भी बदली

Kia ने अपनी कारों के लाइनअप में BS6 Phase2 compliant के हिसाब से बदलाव कर दिया है। इसके पॉवरट्रेन में हुए बदलाव के साथ कीमतें भी बदल गई हैं साथ ही कंपनी ने अपनी कारों के इंजन को E20 ईंधन के अनुकूल बनाया है।

नई दिल्ली। कोरियन कार निर्माता कंपनी Kia ने अपनी दो SUV और एक MPV कार को नए BS6 फेज-2 नियमों के साथ पेश कर दिया है। इनके इंजन को E20 ईंधन के अनुकूल बनाया गया है। साथ ही कंपनी ने 2023 Kia Seltos,Sonet और Carens की कीमतों में भी बदलाव किया है। ये बदलाव नए पॉवरट्रेन के आने की वजह से हुए हैं। हम आपको इन तीनों कारों के नए इंजन और कीमतों बारे में बताने जा रहे हैं।

2023 Kia Seltos, Sonet और Carens का नया इंजन

कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी kia Sonet में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को बरकरार रखा है। साथ ही इसके 1.5 लीटर सीआरडीआई डब्ल्यूजीटी डीजल इंजन को 1.5 लीटर सीआरडीआई वीजीटी के साथ बदल दिया गया है। अब ये इंजन पिछले वाले की अपेक्षा 16 पीएस अधिक पॉवर देता है। वहीं करेंस और सेल्टॉस को नया 1.5 लीटर वाला इंजन दिया गया है।

टाटा मोटर्स की गाड़ियों के पहले से कितनी बढ़ी माइलेज?

ये शक्तिशाली इंजन 160 पीएस की अधिकतम पावर और 253 एनएम का पीक टॉर्क प्रदान करेगा। सेल्टोस और कैरेंस में आने वाला समान पावरट्रेन का पॉवर आउटपुट 1 पीएस से बढ़कर 116 पीएस हो गया है। आपको बता दें कि नए इंजन के साथ इन पूरी रेंज में आईएसजी (आइडल स्टॉप गो) फीचर को स्टैण्डर्ड रूप में दिया गया है।

ये हैं नईकीमतें

नए पॉवरट्रेन के साथ कंपनी ने इन तीनों कार की कीमत भी बदल दी हैं। अब 2023 Kia Sonet को 7.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचा जाएगा, जो कि 14.89 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने kia Seltos की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये रखी है और ये 19.65 लाख रुपये तक जाती है। वहीं Kia Carens को 10.45 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत से लेकर 18.90 लाख रुपये तक रखा गया है।

*नए पॉवरट्रेन के साथ कंपनी ने इन तीनों कार की कीमत भी बदल दी हैं। अब 2023 **Kia Sonet** को 7.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचा जाएगा, जो कि 14.89 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी ने **kia Seltos** की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये रखी है और ये 19.65 लाख रुपये तक जाती है।*

दो ट्रिलियन निर्यात की बड़ी छलांग

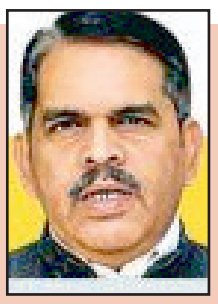

डा. अश्विनी महाजन

देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल देना होगा, लागतों को कम करना होगा और वर्तमान में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को बरकरार रखना होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2013-14 में भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 2 खरब डॉलर से भी कम थी, जो अभी तक बढ़कर 3.5 खरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है।

मार्च 31, 2023 को घोषित विदेश व्यापार नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक 2000 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात शामिल हैं। देश में अभी तक निर्यातों के ढुलमुल प्रदर्शन के चलते, कई विशेषज्ञ इस बड़े लक्ष्य के बारे में शंका व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देश में विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इस लक्ष्य को असाध्य नहीं मान रहा। बल्कि कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि देश इससे कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकता है। दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं, इसे समझना होगा। आज से दस साल पहले 2012-13 में भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात मात्र 452.3 अरब डालर के ही थे। 2012-13 के बाद हमारे आयात तो द्रुत गति से बढ़ते गए, लेकिन निर्यातों के बढने की गति धीमी रही। 2021-22 में हमारे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात हालांकि 683.7 अरब डालर तक पहुंच गए थे, लेकिन आयात 766 अरब डालर पहुंच गए। लेकिन हालांकि आयात इस वर्ष 882 अरब डालर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि निर्यात भी पिछले वर्ष 683.7 अरब डालर की तुलना में, इस वर्ष 767.0 अरब डालर रह सकते हैं। यह सही है कि पिछले 10 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात बहुत तेजी से नहीं बढ़े। लेकिन पिछले साल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात 11.3 प्रतिशत की दर से बढ़ गए। यानी कुछ समय पहले जो 2030 में निर्यातों का 1000 अरब डालर का लक्ष्य भी अभेद्य लग रहा था, 2023 में 2000 अरब डालर का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु देश को निर्यातों के बढने की गति को मात्र 14.81 प्रतिशत ही रखना होगा, जो कि पिछले वर्ष में निर्यातों की ग्रोथ से बहुत ज्यादा नहीं है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

आज जब भारत समेत दुनिया के सभी मुल्क बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं, भारत में महंगाई की दर शेष दुनिया से अभी भी कम है। भारत लगातार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बढ़ती ग्रोथ का असर जीएसटी की प्राप्तियों में दिखाई दे रहा है। हालांकि जीएसटी प्राप्तियों में बड़ा हिस्सा आयात शुल्कों का है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं के आयातों पर मूल्य संवद्र्धन भी जीएसटी में वृद्धि का कारण बन रहा है। यानी ग्रोथ हो या महंगाई पर अंकुश, सभी देश की बढ़ती निर्यात संभावनाओं की ओर इंगित कर रहे हैं।

कैसे बढ़ सकते हैं निर्यात?

यह भी सही है कि दुनिया में चल रही मंदी और

महंगाई के कारण घटती क्रय शक्ति के चलते निर्यातों में वृद्धि करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके बावजूद भारत के सेवाओं और वस्तुओं के निर्यातों में हो रही वृद्धि विशेष महत्व रखती है। देखना होगा कि भारत के निर्यातों में कहां ज्यादा वृद्धि हो रही है। खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि का कुल निर्यातों में विशेष योगदान है। 2021-22 में 50 अरब डालर से अधिक खाद्य निर्यात किए गए। 2022-23 के आंकड़े आना अभी बाकी हैं, लेकिन अभी भी खाद्य निर्यातों में कुल निर्यातों में खासा योगदान बना हुआ है। निर्यातों में वृद्धि में प्रतिरक्षा निर्यातों का बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि अभी तक भारत प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आयातों पर ही अधिक निर्भर रहा है। लेकिन प्रतिरक्षा उद्योग में हुई प्रगति और विशेष तौर पर निजी क्षेत्र के प्रतिरक्षा उद्योग में बढ़ते योगदान के चलते देश न केवल प्रतिरक्षा में उपकरणों में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि इस उद्योग का निर्यातों में भी योगदान बढ़ा है। एक ओर जहां देश अपनी प्रतिरक्षा जरूरतों का 70 प्रतिशत आयातों से प्राप्त करता था, अब मात्र 32 प्रतिशत उपकरणों के लिए ही आयातों पर निर्भर करता है और 68 प्रतिशत प्रतिरक्षा खरीद भारत से हो रही है। पिछले 6 वर्षों में प्रतिरक्षा निर्यातों में 10 गुणा से ज्यादा वृद्धि, भविष्य में इस क्षेत्र के निर्यातों की संभावना को इंगित करती है। गौरतलब है कि 2016-17 में प्रतिरक्षा निर्यात मात्र 1521 करोड़ रुपए के थे, जो 2022-23 में बढ़कर 15920 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। कहा जा सकता है कि भारत का प्रतिरक्षा उद्योग एक ओर विदेशी मुद्रा बचा रहा है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा कमा भी रहा है। बढ़ते विदेशी आर्डरों से प्रतिरक्षा उद्योग में काफी स्पंदन दिखाई दे रहा है। सेवा क्षेत्र में भारत का परचम पिछले 30 वर्षों से लहरा ही रहा है, लेकिन वर्तमान काल में उसका महत्व और बढ़ गया है। 5 वर्षों में ही हमारे सेवाओं के निर्यात 2016-17 में 164.2 अरब डालर से बढ़ते हुए 2021-22 तक 254.5 अरब डालर तक पहुंच गए थे। वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में ये निर्यात 296.9 अरब डालर तक पहुंच चुके हैं और अनुमान है कि 2022-23 के पूर्ण वर्ष के लिए यह आंकड़ा 325 अरब डालर पार कर सकता है। खास बात यह है कि इन निर्यातों में आधे से ज्यादा हिस्सा सॉफ्टवेयर निर्यातों का है। इसके अलावा देश बड़ी मात्रा में बीपीओ, एलपीओ समेत कई प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं का भी निर्यात कर रहा है। देश की सॉफ्टवेयर में प्रगति ने चीन समेत अन्य मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है।

रुपए में व्यापार से भी बदल सकती है तस्वीर

दुनिया के कई मुल्क भारत से आयात करना चाहते भी थे तो भी वे पूर्व में डॉलरों के अभाव के चलते आयात नहीं कर पाते थे। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक पहल की और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र के माध्यम से आयात और निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान निपटारों को रुपयों में करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद दिसंबर में पहली बार रूस के साथ व्यापार का भुगतान रुपयों में करने की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक भारत सरकार के प्रयासों से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और युनाईटेड अरब अमीरात समेत 19 देशों के बैंकों को 'स्पेशल वोस्त्रो रूपी एकाउंट' खोलकर रुपयों में भुगतान निपटारे करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि रुपयों में भुगतान होने के कारण जहां पहले आयात के लिए डॉलर, पाउंड, येन इत्यादि का उपयोग होता था, वे भुगतान रुपयों में होने लगेंगे। इन 19 मुल्कों के साथ अभी भी काफी बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात होता है, रुपयों में भुगतान के चलते इन मुल्कों के पास भारतीय रुपए का स्टॉक बढ़ेगा और वे भारत से ज्यादा सामान आयात कर सकेंगे।

बेहतर होती प्रतिस्पर्धा शक्ति

पूर्व में भारतीय साजो-सामान दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में महंगा माना जाता था, उसका कारण था हमारी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी। पिछले कुछ समय से देश में बिजली की अब कोई कमी दिखाई नहीं देती। उद्योगों को निरंतर बिजली मिल रही है। सौर ऊर्जा इत्यादि के कारण बिजली की लागत में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। सडक़ों के जाल बिछने के कारण अब आवाजाही आसान हो गई है। बेहतर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी भारत की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बना रहा है। ऐसे में जब अभी तक भारत 767 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर चुका है, अगले 7 वर्षों में निर्यात को 2000 अरब डालर तक ले जाना कोई अभेद्य लक्ष्य नहीं लगता। लेकिन देश को इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल देना होगा, लागतों को कम करना होगा और वर्तमान में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को बरकरार रखना होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2013-14 में भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 2 खरब डॉलर से भी कम थी, जो अभी तक बढ़कर 3.5 खरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। वर्ष 2030 में जब हम 7 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे, 2 खरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है।

संपादक की कलम से

जीने-मरने का हक

खुद को संबोधित करने का एक बेहतर तरीका यह भी है कि सामने उपस्थित आशंका को निरस्त कर दो। हिमाचल के मुख्यमंत्री जल उपकर के संबंध में कुछ इसी तरह के अभिप्राय से पंजाब के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर चुके हैं। पानी की क्षमता में कम से कम हिमाचल पड़ोसी राज्यों पर पहली बार भारी पड़ता हुआ, केंद्र सरकार के कानों में रेंगती हुई जूं को देख सकता है। जल उपकर से जुड़ा आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और भविष्य की आर्थिकी का एक मौलिक गठबंधन पैदा हुआ, जो हद और हैसियत का प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल जैसे ही हिमाचल ने पानी की हैसियत बनानी शुरू की है, पड़ोसी राज्यों से लेकर केंद्र तक ने पर्वतीय राज्य को उसकी हद में रहने की एकतरफा प्रतिक्रिया दी है। पहली बार केंद्र सरकार ने ऐसी शर्तें ईजाद की हैं, जिनके तहत राष्ट्रीय विद्युत आबंटन के नए फार्मूले के तहत हिमाचल को दबाव बताया जा रहा है। यानी जो राज्य विद्युत उत्पादन में किसी तरह का उपकर लगाएगा, उसके खाते में राष्ट्रीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में प्राथमिकता नहीं आएगी। इसका सीधा सा अर्थ यह कि आइंदा हिमाचल की विद्युत मांग पर पड़ोसी राज्यों के बनिस्पत निचली पायदान पर विचार होगा। यह एक ऐसी चुनौती है, जो प्रदेश को और हाथ पांव मारने को मजबूर करेगी। हिमाचल का विद्युत उत्पादन सर्दियों में अपनी जरूरतों से कहीं कम हो जाता है और लागत से कहीं महंगी दरों पर इसकी आपूर्ति होती है। हालांकि प्रदेश कई स्तरों पर आपसी समझौते के तहत बिजली का लेनदेन करता है, लेकिन राष्ट्रीय हिस्सेदारी में तयशुदा आपूर्ति पर एक तरह से कट लगने की अप्रत्यक्ष धमकी आ रही है।

यह उस प्रदेश को बताया जा रहा है जो राष्ट्रीय हित में पर्यावरण सुरक्षा के हर उपाय में देश के लिए एक उदाहरण है। कल अगर हिमाचल भी कोयले से बिजली बनाना शुरू करके अपनी आपूर्ति सुनिश्चित कर ले, तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल केंद्र का यह माप तोल सही नहीं है और न ही अब तक केंद्रीय सरकारों ने पर्वतीय राज्यों के लिए ऐसी आर्थिक भरपाई की है, जिसके तहत पर्यावरणीय बंदिशें हमारे हाथ-पांव फिजूल में बांध कर न रख पाएं। सत्तर फीसदी जमीन जंगल के नाम करने का यह अर्थ नाजायज है कि अपने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास भी न किए जाएं। अगर जल उपकर को केंद्र सरकार सही नहीं मानती तो इसकी क्षमता में वित्तीय भरपाई करे तथा प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता के पूर्णदोहन के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दे। हिमाचल को उसी के हालात पर इस तरह नंगा करना सही नहीं है और अगर शर्तें थोंपने का मतलब पर्वतीय ऊर्जा को निहत्था करना है, तो यह नाइंसाफी है। हिमाचल की आत्मनिर्भरता के सामने खड़ी नाइंसाफी की दीवारें, किसी न किसी तरह ढहानी होंगी और इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नागरिक सहयोग भी आवश्यक है। कभी केंद्र हर योजना-परियोजना की फंडिंग का नब्बे फीसदी खर्चा वाहन करके कुछ हद तक न्याय करता था, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसे संकल्पों में उसने यह सीमा 50:50 प्रतिशत कर दी है। इसी तरह की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी पर्वतीय राज्यों की गिनती कमजोर पड़ जाती है।

आश्चर्य यह कि एक तरफ श्रीरेणुका जी बांध परियोजना से हिमाचल पुनः विस्थापन के दंश झेल कर राष्ट्र की प्यास बुझाएगा, जबकि दूसरी ओर नसीहत यह कि इस पानी को यूंही अपने अस्तित्व के ऊपर से गुजर जाने पर भी हाथ-पांव मारने की गुंजाइश न देखे। हिमाचल को अब एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले की नीति पर चलते हुए अपने आर्थिक, भौगोलिक, परंपरागत तथा भविष्यगामी अधिकार पुख्ता करने होंगे। पानी के बाद जंगल और जंगल की जमीन ही हिमाचल को जीने और कमाने का हक दिला सकती है। अगर सामान्य श्रेणी के जंगलों की जमीन को हिमाचल के हित में परखा जाए, तो एक बड़े भाग पर चाय, कॉफी, केनेफ व जट्रोफा के वन उगाकर आर्थिक संबल मिलेगा। हिमाचल के आर्थिक विकास का हर पांव अगर जंगल रोक रहा है, तो हमारा हमेशा 'किस खेत की मूली बनकर' उपहास ही उड़ता रहेगा।

राय

रंग में भंग नहीं पर्यटन

हिमाचल में पर्यटन की खोज में निकला काफिला अगर अटल टनल में मशहूर हो रहा है, तो बीड़-बिलिंग तक पहुंच कर इसकी नई मंजिलें गिनवा रहा है। पैराग्लाइडिंग की महाकल्पना ने पिछले दो दशकों में बीड़-बिलिंग को इसके इरादों का महाकाव्य बना दिया, तो यह दस्तूर प्रदेश की ख्वाहिश में इजाफा कर सकता है। ऐसे में अगले दस या बीस साल बाद हिमाचल के पर्यटन मानचित्र पर कितने नए रंग भरे जा सकते हैं, इसके ऊपर अभी से विचार करना चाहिए। कम से कम नए उभर रहे पर्यटन क्षेत्रों को व्यवस्थित रखने के लिए अभी से प्रयास व परिकल्पना करनी होगी। उदाहरण के लिए अगर पिछले सप्ताह अटल टनल से करीब तीस हजार वाहन गुजर गए, तो हम इस रंग में बदरंग होते मंसूबों को देख सकते हैं। इसी तरह एक प्रतियोगिता ने बीड़-बिलिंग की संभावनाओं को चंद दिनों में निचोड़ दिया। अटल टनल में पर्यटन को एक नए स्तर व मुकाम पर ले जाने की आवश्यकता को जिन शर्तों की जरूरत है, वे सामने नहीं आई हैं, बल्कि यह मनाली का ही विस्तारित पटल हो रहा है। इससे पहले हमने रोहतांग की ढलानों को इतना विद्रूप बना दिया कि एनजीटी को अपनी हिदायतों के कदम वहां रखने पड़े। कुछ इसी तरह बीड़-बिलिंग के पर्यटन इतिहास में हम अति दोहन की निरंकुशता देख सकते हैं। विविधता और भिन्नता के प्रारूप में हिमाचल के हर पर्यटक स्थल को अपनी खूबियां विकसित करनी होंगी। मनाली के बाद अटल टनल भी अगर लाहुल-स्पीति के वातावरण में उसी तरह बसाना चाहे तो यह सही परिप्रेक्ष्य में पर्यटन का विस्तार नहीं होगा। लाहुल-स्पीति के पर्यटन को संवारने से कहीं अधिक सहेजना होगा।

इसी तरह बीड़-बिलिंग के पर्यटन को संवारने के लिए पालमपुर या धर्मशाला के मॉडल का अनुसरण करना गैरजरूरी है। इतना ही नहीं बीड़ और बिलिंग के बीच गतिविधियों का बंटवारा अगर सही नहीं होगा, तो एक दिन बिलिंग खुद को बीड़ या पालमपुर बनाते हुए बड़ा लक्ष्य खो देगा। पिछले कई दशकों से पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी व्यय बढ़ा है, लेकिन लक्ष्यों का बंटवारा नहीं हुआ, लिहाजा कहीं सरकारी होटल और कहीं निजी पर्यटन इकाइयां एक दूसरे से भिड़ रही हैं। पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल बेशक एशिया विकास बैंक की मदद से बढ़ा है, लेकिन क्या इससे नतीजे बेहतर हुए या सारा व्यय अनुपयोगी हो गया। पूरे प्रदेश में राजनीतिक दखल से खड़े की गई कई इकाइयां धूल चाट रही हैं या अप्रासंगिक होकर केवल अपव्यय का पर्याय बन गई हैं। वर्तमान सरकार को अगले बीस सालों का खाका बनाते हुए पिछले बीस सालों का अपना इतिहास भी जान लेना चाहिए। प्रदेश में कितनी पर्यटन इकाइयां क्यों असफल हुईं या इनके औचित्य पर प्रश्न क्यों खड़े हुए, इससे सीखते हुए आगे बढऩा चाहिए। इतना ही नहीं हिमाचल की प्रगति ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी पर्यटन के रास्तों पर खड़ा कर दिया है, जहां विशेष योजनाओं के तहत हाई-वे पर्यटन, युवा एवं छात्र पर्यटन, सिने पर्यटन व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। इसी लक्ष्य से नादौन से भोटा के बीच साइंस सिटी, बीबीएन में टेक्नोलॉजी पार्क, नदियों के किनारे वाटर स्पोर्ट्स तथा पूरे प्रदेश में साहसिक पर्यटन का एक जाल बुनना होगा। उदाहरण के लिए बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की अनुमति तब दी जाए अगर पर्यटक इससे पूर्व किसी आरंभिक प्लैटफार्म पर अनुभव प्राप्त करके आया हो, यानी सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, चंबा व मंडी में पैराग्लाइडिंग की सरलता में कम से कम जोखिम वाली पहाडियों पर इन्हें आरंभिक तौर पर अवसर दिया जाए। पिछली सरकार ने तत्तापानी के धार्मिक महत्त्व को वाटर मनोरंजन रिजोर्ट के रूप में विकसित किया था, लेकिन इसे एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। अतीत में स्की विलेज की परिकल्पना पर सियासी चाबुक का प्रहार हमारी क्षमता, योग्यता व संभावना से कुठाराघात कर गया और कुछ इसी तरह पौंग जलाशय की विराटता और एयरपोर्ट की समीपता को नजरअंदाज करते हुए हिमाचल ने अवसर गंवाए हैं।

प्रो. सुरेश शर्मा, लेखक

भारतीय संगीत परंपरा एवं सुरों के राजन

> "बहुत ही दुःख की बात है कि दुनिया का यह विद्वान शास्त्रीय संगीत गायक, खूबसूरत चेहरा एवं बेहतरीन इनसान आज

भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान संगीत परम्परा में अनेकों श्रेष्ठ तथा धुरंधर संगीतज्ञों ने देश की कला एवं संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय संगीत की इस महान घराना परम्परा को विभिन्न गायकों एवं वादकों ने अपनी कला साधना एवं तपस्या से भविष्य की पीढियों के लिए सुरक्षित रखा है। बीसवीं शताब्दी में कुछ ऐसे ही महान गायक हुए हैं जिनमें हम संगीत सम्राट तानसेन जैसे संगीतज्ञ का अक्स देखने की परिकल्पना करते हैं। इन गायकों में अब्दुल करीम खान, सवाई गंधर्व, गंगू बाई हंगल, फैयाज खान, अमीर खां साहब, डीवी पलुस्कर, केसरबाई केरकर, मोगुबाई कुर्डीकर, हीरा बाई बड़ोदकर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, पण्डित ओमकार नाथ ठाकुर, पण्डित दिलीप चन्द्र बेदी, कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, पण्डित भीमसेन जोशी, पण्डित जसराज जैसे बेजोड़ गायक हुए हैं। इसी के साथ बाबा अलाउद्दीन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पण्डित रवि शंकर, उस्ताद विलायत खां, अल्ला रक्खा, अली अकबर खां, पण्डित शिव कुमार, हरि प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन तथा अमजद अली खां जैसे महान संगीतज्ञों ने भारतीय संगीत परम्परा को विश्व भर में अलोकित किया। इसी कड़ी में बनारस घराने के बेजोड़, विख्यात एवं अद्वितीय गायक पंडित राजन मिश्रा थे, जिनका निधन दो वर्ष पूर्व 25 अप्रैल, 2021 को रविवार के दिन हुआ। संगीत के बनारस घराने को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले शास्त्रीय गायन के पुरोधा पंडित राजन मिश्रा के देहांत की खबर सुनकर पूरे देश के शास्त्रीय संगीत प्रेमी स्तब्ध रह गए।

पंडित राजन मिश्रा हृदय की खराबी, उस पर वे कोरोना वायरस संक्रमण से हार गए। नाद ब्रह्म का यह महान साधक, संगीतज्ञ एवं सरस्वती पुत्र सदा-सदा के लिए संगीत जगत से विदा होकर ब्रह्म लोक में लीन हो गया। इसके साथ ही राजन-साजन मिश्रा नाम से शास्त्रीय संगीत की विश्व विख्यात जोड़ी टूट गई। लगभग 400 वर्षों की बनारस घराने में शास्त्रीय संगीत की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इन दोनों भाइयों को बहुत ही आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। पंडित राजन को उनके दादा पंडित बड़े राम जी मिश्रा तथा पिता पंडित हनुमान मिश्रा से संगीत शिक्षा मिली थी। पंडित राजन का विवाह पंडित दामोदर की पुत्री श्रीमती बीना से हुआ। वर्तमान में राजन मिश्रा के पुत्र रितेश मिश्रा एवं रजनीश मिश्रा भी शास्त्रीय संगीत गायक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित एवं स्थापित कर चुके हैं। पंडित राजन मिश्रा के गायन का अंदाज, भाव-भंगिमाएं, स्वर लगाव, लयकारी, बहलावे, स्पाट तान, गमक, मींड, तार सप्तक में स्वर प्रयोग, रागदारी, ताल प्रयोग, बंदिशों को प्रस्तुत करने का तरीका, क्या कहने, संगीत प्रेमियों को हृदय से छू लेता था। पंडित राजन मिश्रा को अपने घराने की परम्परा तथा संगीतज्ञों पर बहुत ही गर्व था। अपने संगीत के कार्यक्रमों में वे बनारस घराने की अनेकों रागों में तथा विभिन्न तालों में निबद्ध रचनाओं को बड़े ही शौक से सुनाते थे। यह जोड़ी मंच पर बैठी इस तरह प्रतीत होती थी मानो गंधर्व लोक से कोई देव, ऋषि या फिर गंधर्व गायक युगल गायन की वर्षा कर रहा हो। धोती-कुर्ते के आकर्षक परिधान में ठहरी और गहरी बातचीत, विद्वान एवं विशाल व्यक्तित्व, संगीत और ज्ञान का अथाह सागर, संगीत सागर के मनन, चिंतन एवं मंथन में निरंतर डूबे हुए एक आदर्श उदाहरणीय एवं अनुकरणीय संगीतज्ञ की जोड़ी ने एक सच्चे संगीतज्ञ को परिभाषित किया है। पंडित राजन मिश्रा ज्ञान, शास्त्र और संगीत के ठहरे हुए समुद्र थे।

धीर-गंभीर, शांत व्यक्तित्व के स्वामी पंडित राजन अपने जोड़ीदार पंडित साजन मिश्रा के लिए बड़े भाई के साथ-साथ एक गुरु, पिता तुल्य व्यक्तित्व एवं मार्गदर्शक थे। अपनी प्रस्तुतियों में अनेकों बार साजन मिश्रा मंच पर बैठे हुए अपने बड़े भाई पंडित राजन का गायन सुनते रहते तथा सीखते रहते तथा अपने आप को एक शिष्य की तरह देखते। सन- 1951 में जन्मे राजन मिश्रा को विरासत से ही बनारस घराने की विशाल संगीत परंपरा प्राप्त हुई। इस संगीतज्ञ जोड़ी ने वर्ष 1978 में श्रीलंका में अपना पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, रूस, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, सिंगापुर, कतर, बांग्लादेश और दुनिया के कई महानगरों में अपनी शास्त्रीय गायकी से संगीत प्रेमियों को रिझाया। खयाल गायन के साथ-साथ पंडित राजन तराना, टप्पा, ठुमरी तथा भजन गायकी में भी बेमिसाल थे। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा टीवी के लगभग सभी कार्यक्रमों में इस गायक युगल का गायन होता रहता था। प्रत्येक प्रस्तुति के पश्चात श्रोताओं की इनसे भजनों की फरमाइश जरूर रहती। पंडित राजन मिश्रा को राग अहीर भैरव, बिलासखानी, तोड़ी, भैरव, भैरवी, गुजरी तोड़ी, वृंदावनी सारंग, पूरिया, मारवा, श्री, दरबारी कान्हड़ा, मालकौंस आदि अनेक रागों पर पूर्ण अधिकार था।

'अब कृपा करो श्री राम दुख से हमें उबारो', 'जय-जय दुर्गे माता भवानी', 'साधो ऐसा ही गुरु भावे', 'चलो मन वृंदावन की ओर', 'अब तो शाम नाम लौ लागी', 'धन्य भाग सेवा का अवसर पाया', 'जगत में झूठी देखी प्रीत' जैसे भजनों को संगीत जगत कभी नहीं भूल सकेगा। शास्त्रीय संगीत गायन में खयाल, टप्पा तथा भजन की अनेकों एल्बम संगीत जगत को दी। भारत में लगभग हर शहर में उन्होंने शास्त्रीय संगीत के श्रोताओं को अपनी प्रस्तुतियों से रिझाया। वे करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते थे। पंडित राजन-साजन मिश्रा को सन- 1971 में प्रधानमंत्री द्वारा संस्कृति पुरस्कार, 1995 में राष्ट्रीय सम्मान, 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2007 में पदम विभूषण तथा 2011-12 में तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित राजन मिश्रा का संगीत जगत से असमय विदा हो जाना शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा आघात है। पंडित राजन मिश्रा जैसा उत्कृष्ट कलाकार तथा बेहतरीन इनसान मिलना आसान नहीं है। बहुत ही दुःख की बात है कि दुनिया का यह विद्वान शास्त्रीय संगीत गायक, खूबसूरत चेहरा एवं बेहतरीन इनसान आज हमारे बीच में नहीं है। संगीत जगत में इस सूर्य का डूबना बहुत ही दुखद है। संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। पंडित राजन मिश्रा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे सदियों तक संगीत प्रेमियों के हृदय में अमर रहेंगे।

चिंतन विचार

छिलकों की छाबड़ी : डिग्री का खेल

मंत्री केन्द्रीय हो तो उसका कोई बाल भी बींका नहीं कर सकता। अगर प्रदेश सरकार किसी छोटे-मोटे राजनीतिक दल की हो तो उसका कानून मंत्री भी संतरी बन कर रह जाता है। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार के कानून मंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की मिसाल हमारे सामने है।

प्रधानमंत्री की डिग्री पर बवाल उठने से पहले मुझे लगता था कि डिग्री का खेल सिर्फ मौसम खेलता है। जब उसका मन होता है गर्मियों में पारा 50 डिग्री पर लाकर पटक देता है या सर्दियों में माईनस डिग्री से भी नीचे खींच लेता है। अनगिन आदमियों को अपनी डिग्री के जाल में उलझा कर मौसम हरारत या ठंड से मौत के आगोश में सुला देता है। पर आजकल तो पूरा देश डिग्री-डिग्री खेल में मस्त है। आम आदमी से लेकर नेता, चमचे, कर्मचारी और यहां तक कि जज भी डिग्री-डिग्री खेल रहे हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि जब भी कोई डिग्री का नाम लेता है, लोग संशय से इधर-उधर देखने लगते हैं। केन्द्र सरकार के मंत्री और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता एक स्वर में विरोधियों के खिलाफ हू-हू करने लगते हैं। संवैधानिक संस्थाएं व्यक्तिगत डिग्री की गरिमा बनाए रखने के लिए कदमताल करने लगती हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने वाले आप के नेता का पाप तो हमेशा आँखों पर काली पट्टी बाँधे रखनी वाली न्याय की देवी ने जुर्माना लगा कर धो दिया। पर संभव है कि आने वाले समय में आर्यावर्त में प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने वालों पर देशद्रोह का मुकद्दमा ठुक जाए। पर डिग्री की डिग्री सत्ता अर्थात सरकारों की ताकत पर निर्भर करती है।

मंत्री केन्द्रीय हो तो उसका कोई बाल भी बींका नहीं कर सकता। अगर प्रदेश सरकार किसी छोटे-मोटे राजनीतिक दल की हो तो उसका कानून मंत्री भी संतरी बन कर रह जाता है। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार के कानून मंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की मिसाल हमारे सामने है। पर मुई डिग्री की नाक है कि कटने के बाद भी नेता की नाक की तरह अकाट्य बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भगवान श्रीराम लक्ष्मण को सूर्पणखा की नाक की तरह डिग्री की नाक काटने के लिए कहें तो

अब वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे। वर्तमान राष्ट्रीय परिवेश को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि डिग्री के महत्व को कायम रखने के लिए सरकार संस्कृति, पुराणवाद, राष्ट्रवाद, गौभक्ति, बुलडोजर, ईमानदारी और देशभक्ति पर राजनीति शास्त्र के एकमात्र वैश्विक कोर्स 'एंटायर पॉलिटिकिस साईंस' की तरह कोई नया डिग्री कोर्स आरम्भ करे।

प्रधानमंत्री ने एक बार जंगी जहाज को राडार की आँख से बचाने की तरकीब तो बताई थी, पर डिग्री बताना भूल गए थे। अगर लगे हाथ यह भी बता देते कि किस डिग्री पर जहाज़ को बादलों के बीच उड़ाने से उसे राडार की आँख से बचाया जा सकता है, तो उस साल के लिए फिज़िक्स के नोबेल प्राईज़ के हक़दार हो सकते थे। पर चिंता की कोई बात नहीं। युगपुरुष के पास नए-नए सुझावों और प्रयोगों की लम्बी फेरहिस्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नोटबंदी, गंदे नाले की गैस से चाय-पकौड़े बनाने, हवा से पानी बरसाने, वैश्विक शांति क़ायम करने के उपाय जैसे हज़ारों उपयोगी सुझावों से वह शीघ्र ही किसी भी क्षेत्र या विषय में नोबेल पुरस्कार से अलंकृत होकर राष्ट्र को नई गरिमा और ऊर्जा से गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने नोबेल प्राईज़ मिलने पर कहा था कि वह इस पुरस्कार को ग्रहण करने के बाद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। पर इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार दिए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार शर्मिंदगी महसूस करे कि वह उन्हें नवाजने में इतनी लेट क्यों हो गया। हो सकता है किसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से आग्रह करें कि जिस तरह कुछ अरसा पहले उन्होंने कोरोना को दीपक दिखाया था, उसी तरह डिग्री को दीपक दिखाएं या घोषणा कर दें कि अगर किसी विशेष दिन, ख़ास मुहूर्त में जो देशवासी ताली-थाली की तरह अपनी डिग्रियाँ हवा में तीन सौ साठ डिग्री में घुमाएंगे, उनकी डिग्रियों पर प्रश्न उठाने वालों पर देशद्रोह का मुकद्दमा दायर किया जाएगा।

पीए सिद्धार्थ

अडानी ग्रुप के बाद TCS और Infosys पर संकट! अमेरिका के रीजनल बैंकों में है सबसे ज्यादा एक्सपोजर

पी.वी. न्यूज

अमेरिका में एक हफ्ते के भीतर दो रीजनल बैंक डूब चुके हैं। अमेरिका से शुरू हुआ यह संकट यूरोप पहुंच चुका है। यह भारत की आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। जेपी मोर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रीजनल बैंक्स में टीसीएस और इन्फोसिस का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। बैंकिंग संकट से इन कंपनियों की परेशानी बढ़ सकती है।

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार अभी तक अडानी ग्रुप (Adani Group) के संकट से भी पूरी तरह नहीं उबर पाया है कि एक और मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अमेरिका से शुरू बैंकिंग संकट (Banking Crisis) यूरोप पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि यह आगे और गहरा सकता है। इस बीच जेपी मोर्गन (JPMorgan) के एनालिस्ट्स का कहना है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे अमेरिका के बैंकों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर भारत की दो बड़ी आईटी कंपनियों टीसीएस (TCS) और इन्फोसिस (Infosys) का है। उनके कुल रेवेन्यू में अमेरिका के रीजनल बैंक्स की हिस्सेदारी 2-3 फीसदी है। हाल में डूब गए सिलिकॉन वैली बैंक में टीसीएस, इन्फोसिस और माइंडट्री (Mindtree) का एक्सपोजर 10 से 20 बेसिस पॉइंट हो सकता है। इसमें टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी टीसीएस का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मोर्गन ने एक नोट में कहा कि इन तीनों कंपनियों को सिलिकॉन वैली बैंक में अपने एक्सपोजर के लिए प्रॉविजन करना पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के डूबने तथा अमेरिका और यूरोप में लिक्विडिटी की चिंताओं बैंक शॉर्ट टर्म में अपने टेक बजट को कम कर सकते हैं। देश की आईटी इंडस्ट्री पहले ही यूरोप और अमेरिका में मैक्रोइकॉनमिक एनवायरमेंट की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के कारण डिमांड कम हुई है। इस कारण कंपनियां टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर रही हैं। बैंकिंग क्राइसिस से स्थिति और बदतर हो सकती है। इस कारण अगली कुछ तिमाहियों में आईटी कंपनियों का रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है।

किससे आता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू

भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे ज्यादा रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर से आता है। इस सेक्टर में अमेरिकी बैंकों में उनका एक्सपोजर औसतन 62 फीसदी और यूरोप में 23 फीसदी है। माइंडट्री ने हाल में कहा था कि एसवीबी समेत अमेरिकी बैंकों में उसका एक्सपोजर मामूली है।

रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

राजदूत ने ट्वीट कर दिग्गज के बारे में ये कहा

भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फैरेल ने सप्ताहांत पर ट्विटर पर इसकी पुष्टि की। फैरेल ने रतन टाटा को 'व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत का दिग्गज' बताया। उन्होंने कहा कि टाटा के योगदान ने ऑस्ट्रेलिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

नई दिल्ली। उद्योगपति और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फैरेल ने सप्ताहांत पर ट्विटर पर इसकी पुष्टि की। फैरेल ने रतन टाटा को 'व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत का दिग्गज' बताया। उन्होंने कहा कि टाटा के योगदान ने ऑस्ट्रेलिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ओ फैरेल ने शनिवार को ट्वीट किया, ₹रतन टाटा न केवल भारत में व्यापार, उद्योग और परोपकार के दिग्गज हैं, बल्कि उनके योगदान ने ऑस्ट्रेलिया में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के प्रति रतन टाटा की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (एओ) सम्मान प्रदान करते हुए खुशी हो रही है।

इनसाइड

कहीं काम के दबाव में ऑफिस में सो रहे लोग, ये कंपनी सोने की दे रही छुट्टी, वो भी भारत में

नई दिल्ली: ऑफिस में कर्मचारियों को कई तरह की छुट्टी दी जाती हैं। इसमें सिक लीव, ईएल और सीएल शामिल होती हैं। लेकिन कई बार ऑफिसों में काम के दबाव के बीच लोगों को छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें ट्विटर (Twitter) की एक कर्मचारी ऑफिस में बिस्तर लगाकर सोते हुए दिख रही थी। लेकिन अगर किसी ऑफिस में आपको सोने के लिए भी छुट्टी दी जाए तो आप क्या कहेंगे। एक कंपनी अपने कर्मचारियों को सोने के लिए छुट्टी दी है। ये कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि भारत की कंपनी है। आज वर्ल्ड स्लीप डे (World Sleep Day 2023) पर बेंगलुरु की कंपनी ने अपने कर्मचारियों को यह अनोखा गिफ्ट दिया है। बेंगलुरु की एक फर्म ने अपने कर्मियों को अनोखा गिफ्ट दिया है। कंपनी ने इंटरनेशनल स्लीप डे (World Sleep Day 2023) पर सभी को छुट्टी दे दी है ताकि वे सो सकें। कंपनी ने कहा कि उसे यह घोषणा करते हुए काफी खुशी हो रही है कि शुक्रवार 17 मार्च 2023 को अंतराष्ट्रीय नींद दिवस के मौके पर वैकल्पिक छुट्टी दी गई है।

सोने में 180 रुपये की गिरावट, चांदी 240 रुपये कमजोर हुई

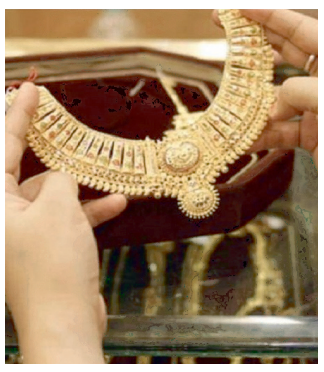

नई दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 180 रुपये की गिरावट के साथ 60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इस दौरान चांदी भी 240 रुपये गिरकर 75,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कमजोर वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 180 रुपये की गिरावट के साथ 60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,480 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी भी 240 रुपये गिरकर 75,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 180 रुपये की गिरावट के साथ 60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, "कीमतों में हालिया गिरावट के बाद और अक्षय तृतीया से पहले घरेलू बाजार में सोने की मांग में सुधार होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी गिरावट के साथ क्रमशः 2,003 डॉलर प्रति औंस और 25.15 डॉलर प्रति औंस कारोबार करते दिखे।

कांग्रेस ने धरावी परियोजना अदाणी समूह को सौंपे जाने पर सवाल उठाए, पूछा- क्यों बदली निविदा की शर्तें

हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रहा है।

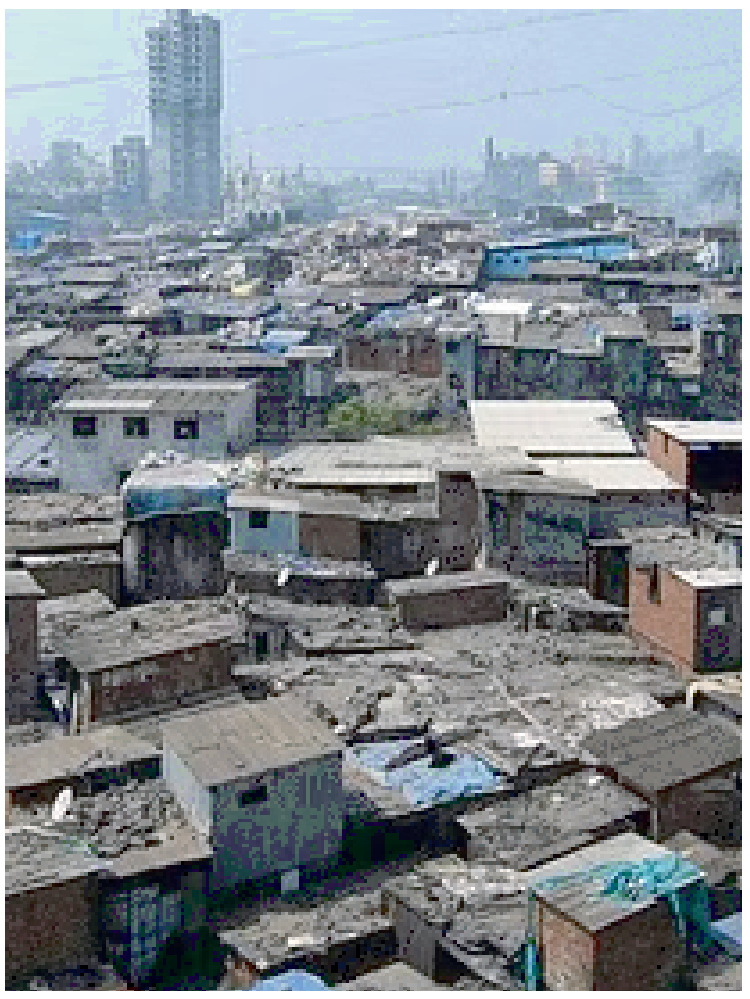

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार की धारावी परियोजना से पिछले विजेता को जानबूझकर बाहर किया गया है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या निविदा की शर्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पसंदीदा कारोबारी समूह' अदाणी को मदद पहुंचाने के लिए बदला गया है?

कांग्रेस अदाणी समूह के खिलाफ जेपीसी जांच की कर रही मांग

बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि वे सभी कानूनों और डिस्क्लोजर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

कांग्रेस ने पूछा-कम बोली पर अदाणी समूह को कैसे दे दी गई परियोजना?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि फरवरी में कांग्रेस पार्टी ने 'हम अदाणी के हैं कौन(एचएएचके)' श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री मोदी से धारावी के लिए लगने वाली बोली की शर्तों में बदलाव के बारे में बताने को कहा था। इन्हीं बदलावों के तहत मुंबई के धारावी क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए निविदा के पिछले विजेता को बाहर कर दिया गया था। पिछली विजेता को बाहर कर अदाणी समूह को बहुत कम बोली पर एक नई निविदा जीतने की अनुमति दे दी गई थी।

भारतीय दूतावास ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए घर पर ही रहने की अपील

भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लूटपाट की कई घटनाएं सामने आईं हैं। ऐसे में आम लोगों को दूतावास की ओर से सलाह दी गई है कि आप पर्याप्त राशन सामग्री का इंतजाम कर लें।

नई दिल्ली। सूडान के खार्तूम में भारतीय दूतावास ने लूटपाट की कई घटनाओं को देखते हुए वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई है। भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लूटपाट की कई घटनाएं सामने आईं हैं। ऐसे में आम लोगों को दूतावास की ओर से सलाह दी गई है कि आप पर्याप्त राशन सामग्री का इंतजाम कर लें। अगले कुछ दिनों में यही स्थिति बनी रह सकती है। अपने पड़ोसियों से मदद हासिल करने की कोशिश करें। अपने घरों पर ही रहें और सुरक्षित रहें।

वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट : यूपीआई से हुए 126 लाख करोड़ के लेनदेन, 54 फीसदी इजाफा

वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-दिसंबर, 2022 में यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड व प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे साधनों से कुल 149.5 लाख करोड़ के 87.92 अरब लेनदेन हुए। इसमें यूपीआई पर्सन-टु-मर्चेंट (पी2एम) और यूपीआई पर्सन-टु-पर्सन (पी2पी) पसंदीदा भुगतान माध्यम रहे।

नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान का चलन कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इसमें यूपीआई की बड़ी भूमिका रही है। पिछले साल यानी 2022 में यूपीआई से 126 लाख करोड़ रुपये के 74 अरब लेनदेन हुए। सालाना आधार पर ये आंकड़े मूल्य के लिहाज से 54 फीसदी व संख्या के हिसाब से 70 फीसदी ज्यादा हैं।

वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-दिसंबर, 2022 में यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड व प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे साधनों से कुल 149.5 लाख करोड़ के 87.92 अरब लेनदेन हुए। इसमें यूपीआई पर्सन-टु-मर्चेंट (पी2एम) और यूपीआई पर्सन-टु-पर्सन (पी2पी) पसंदीदा भुगतान माध्यम रहे। यूपीआई पी2पी की हिस्सेदारी मूल्य और संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा क्रमशः 44 फीसदी एवं 66 फीसदी रही।

पीओएस मशीन से लेनदेन में यूपी, दिल्ली और पंजाब शीर्ष-10 में : देशभर में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की संख्या दिसंबर, 2022 तक 37 फीसदी बढ़कर 75.5 लाख इकाई पहुंच गई। सबसे ज्यादा पीओएस लगाने वाले राज्यों के लिहाज से शीर्ष-10 में यूपी 5वें, दिल्ली 6वें और पंजाब 10वें स्थान पर है।

डिजिटल भुगतान में दिल्ली दूसरे स्थान पर

शहर	संख्या	मूल्य
बंगलूरू	2.9	65
दिल्ली	1.96	50
मुंबई	1.87	49.5
पुणे	1.5	32.8
चेन्नई	1.43	35.5

(संख्या : करोड़ में, मूल्य : अरब रुपये में)

वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-दिसंबर, 2022 में यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड व प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे साधनों से कुल 149.5 लाख करोड़ के 87.92 अरब लेनदेन हुए। इसमें यूपीआई पर्सन-टु-मर्चेंट (पी2एम) और यूपीआई पर्सन-टु-पर्सन (पी2पी) पसंदीदा भुगतान माध्यम रहे।

शीर्ष-5 बैंकों से सर्वाधिक भुगतान

एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक।

शीर्ष-5 बैंकों को सबसे ज्यादा भुगतान

पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यस बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक।

रिपोर्ट की अन्य खास बातें...

1.02 अरब क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी हुए हैं दिसंबर, 2022 तक

13.12 लाख करोड़ के 2.76 अरब लेनदेन हुए क्रेडिट कार्ड से

7.4 लाख करोड़ रुपये के 3.64 अरब लेनदेन हुए डेबिट कार्ड से

मोबाइल वॉलेट से 2.25 लाख करोड़ रुपये के 5.87 अरब लेनदेन हुए

आधार आधारित भुगतान सेवा से 2022 में 2.63 अरब लेनदेन हुए, जिसका मूल्य 3.42 लाख करोड़ रुपये रहा।

वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-दिसंबर, 2022 में यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड व प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे साधनों से कुल 149.5 लाख करोड़ के 87.92 अरब लेनदेन हुए। इसमें यूपीआई पर्सन-टु-मर्चेंट (पी2एम) और यूपीआई पर्सन-टु-पर्सन (पी2पी) पसंदीदा भुगतान माध्यम रहे।

लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 183 अंक टूटा, निफ्टी 17700 के नीचे

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स मंगलवार को 183.74 (0.31%) अंकों की गिरावट के साथ 59,727.01 अंकों के लेवल पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 46.70 (0.26%) अंकों की गिरावट के साथ 17,660.15 अंकों के लेवल पर पहुंच गया। मंगलवार को बाजार की गिरावट के दौरान बाजार में ऑयल एंड गैस और कंज्युमर ड्यूरेबल्स के शेयरों में कमजोरी दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस के शेयर मंगलवार को 27.05 (1.14%) रुपये की गिरावट के साथ 2,340.40 रुपये के भाव पर कारोबार करते दिखे। पावर ग्रिड के शेयर 2.60% तक टूटे।

27 अप्रैल से कर्नाटक के रण में उतरेंगे पीएम मोदी

ताबड़तोड़ करेंगे 16 सभाएं और रोड शो

उपेंद्र पाटोदिया

भाजपा सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक राज्य इकाई की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की 32 रैलियों की मांग की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री की अन्य व्यवस्तताओं को देखते हुए अभी तक 16 जनसभाओं-रोड शो की अनुमति दी गई है...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल से कर्नाटक के चुनावी रण में कूदने जा रहे हैं। वे 27 अप्रैल को वर्चुअल तरीके से कर्नाटक के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 28 अप्रैल से उनकी जनसभाओं और रोड शो का दौर शुरू होगा, जो सात मई तक चलेगा। इस दौरान वे लगभग 16 जनसभाएं-रोडशो को आयोजित कर भाजपा के पक्ष में चुनावी हवा को बदलने की कोशिश करेंगे।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक राज्य इकाई की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की 32 रैलियों की मांग की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री की अन्य व्यवस्तताओं को देखते हुए अभी तक 16 जनसभाओं-रोड शो की अनुमति दी गई है। ये सभाएं 28-29 अप्रैल, तीन मई, चार मई, छह मई और सात मई को आयोजित की जाएंगी। ये सभाएं पार्टी के द्वारा उतारे गए नए उम्मीदवारों और लिंगायतों की बहुमत आबादी वाले इलाकों के साथ-साथ पूरे कर्नाटक में होंगी।

कर्नाटक में भाजपा को लिंगायत नेताओं की नाराजगी के कारण नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सत्ता में रहने के कारण एंटी इन्कमबेंसी फैक्टर को भी भाजपा के विरुद्ध बताया जा रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीन पर उतरने के बाद पूरी चुनावी हवा भाजपा के पक्ष में हो जाएगी। पार्टी को उम्मीद है कि वह कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रहेगी।

मानहानि मामले में सजा माफी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा माफी के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें सूरत की एक निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

किस मामले में हुई राहुल को सजा?

राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थ्रीं, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी पर तीन मई को सुनवाई होनी है।

राहुल ने क्या कहा था?

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राहत नहीं मिली तो राहुल के लिए आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायकी-सासंदी चली जाती है। इसके साथ ही अगले छह साल के लिए वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। राहुल की सांसदी चली गई है। अगर कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।

नियम क्या कहते हैं?

दरअसल, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक-प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक, आपराधिक मामले में (दो साल या उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाली धाराओं के तहत) दोषी करार किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उस सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था, अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर कर दी गई हो। यानी धारा 8(4) दोषी सांसद, विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट प्रदान करती थी।

महाराष्ट्र की 'पोस्टर राजनीति', धाराशिव में लगे अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले बैनर

पवार ने कहा कि '2024 क्यों, हम अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा करने को तैयार हैं।' अजित पवार ने ये भी कहा कि 'वह 100 फीसदी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे।'

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि वहां पर्दे के पीछे काफी कुछ घटित हो रहा है। अब इस बीच एक नया घटनाक्रम घटित हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के धाराशिव में अजित पवार को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर-बैनर जगह-जगह लगे हैं। धाराशिव में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर उनके उस बयान के बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी।

क्या बोले अजित पवार

दरअसल मीडिया से बातचीत में अजित पवार से सवाल किया गया कि क्या एनसीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करेगी? इस पर पवार ने कहा कि '2024 क्यों, हम अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा करने को तैयार हैं।' अजित पवार ने ये भी कहा कि 'वह 100 फीसदी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे।'

अपने अंतिम क्षण तक एनसीपी में रहूंगा- अजीत पवार

अजीत पवार ने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर चल रही अफवाहों के बीच एक बार फिर एनसीपी में ही रहने की बात दोहराई है। मंगलवार को उन्होंने दोहराया कि वह अपने अंतिम क्षण तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में बने रहेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी के एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कई तरह की अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन किसी भी अफवाह का शिकार हुए बिना मैं अपना काम जारी रख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं अपने अंतिम समय तक एनसीपी में काम करता रहूंगा।

भाजपा के साथ जाने की थी अटकलें

बीते दिनों अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की भी अटकलें चल रहीं थी। ये अटकलें इतनी ज्यादा थीं कि शिवसेन नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी इस पर सफाई देनी पड़ी थी। एनसीपी के कुछ विधायक भी खुलकर अजित पवार के समर्थन में खड़े दिखे। हालांकि बाद में अजित पवार ने ही इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अजित पवार ने कहा था कि जब तक जान में जान है, तब तक वह एनसीपी से जुड़े रहेंगे। इससे पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले अजित पवार ने नाटकीय तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर उप-मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। हालांकि गाहे-बगाहे अजित पवार के भाजपा के साथ जाने की खबरें राजनीतिक गलियारों में आती रहती हैं।

रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन कोई उपकार नहीं, मंच ने वृंदावन से दी हजारों पैंशन भोगियों की चेतावनी

एस डी सेठी

नई दिल्ली। भारतीय पेंशन मंच' के छठे स्थापना दिवस पर वृंदावन यूपी में आयोजित समारोह में मंच के महासचिव वीरेंद्र सिंह यादव ने देश के 19 राज्यों से आए हजारों यूनियन कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार को चेताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन कोई उपकार नहीं है, बल्कि सेवाकाल के 60 वर्षों के दौरान कर्मचारियों के द्वारा किए कठोर परिश्रम का प्रतिफल है। जो उनका आर्थिक रूप से सुरक्षा कवच भी है। मंच के महासचिव वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा हालांकि पैंशनर अपने सेवाकाल में मिले वेतन पर आयकर पहले ही दे चुके हैं। फिर भी उनकी पेंशन पर आयकर लगाया जाता है। दूसरी ओर विधायकों, सांसदों, पार्षदों को मिलने वाली पेंशन पर कोई आयकर नहीं लगाया जाता है। यूनियन महासचिव ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह का आखिर भेद भाव क्यों? यूनियन नेता ने सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल भाड़े में मिल रही छूट को कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दिया गया। जिस छूट पर आज तक पाबंदी लगाई हुई है।यह कतई न्याय संगत नहीं है। जबकि सांसदों, विधायक, व अन्य वर्गो के लिए यह रियायत जारी है।

दूसरी और कोरोना काल में ही तब सेवारत रहे लाखों कर्मचारियों समेत पेंशन भोगियों का 18 फीसदी मंहगाई भत्ता तक रोक दिया गया था। जिसका हालात समान्य होने के बाद भी महगाई भत्ते का भुगतान पेंडिंग है। जबकि सरकार अपने खर्चो में कोई कटौती नहीं कर रही है। यूनियन नेता ने कहा कि कई अन्य मुद्दे भी हैं, यूनियन समय-समय पर सरकार के सामने उठाता रहा है। लेकिन सरकार ने उन तमाम मुद्दो को दरकिनार कर ठंडे बस्ते मे डाल दिया है। यूनियन ने पेंशन भोगियों के प्रति सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये पर कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। यूनियन नेताओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि

सरकार ने 2024 से पहले अगर इस बावत कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो मंच भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी।

इसी क्रम में भारतीय पेंशन मंच के प्रवक्ता विनोद पराशर ने बताया कि यूनियन के 5वें स्थापना अवसर पर 70-80 वर्ष से अधिक आयु पूरी करने वाले अपने सदस्यों को विशेष रूप से' 'पेंशन रत्न सम्मान 2023' के तहत उन्हें पटके व पगडी पहनाकर प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया द गया। इसके अलावा मंच के लिए विशेष योगदान देने वाले सदस्यों को भी सम्मानित भी किया गया।

डॉ विनोद भट्ट को मिली बंदूक से उड़ाने की धमकी, मामला रतलाम की प्रापर्टी

जिला ब्यूरो चीफ उपेंद्र पाटोदिया

रतलाम। प्राप्त जानकारी अनुसार रतलाम में परख पैथोलॉजी लैब संचालक डॉ विनोद भट्ट को बंदूक से उड़ाने की धमकी मिल रही हैं क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार परेशान करते हुए आज डॉक्टर विनोद भट्ट के अनुसार रमेश चौरडिया, भरत चौरडीया, सोनू चोरडीया टोनू चोरडीया द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है और हालाकि यह विवाद न्यायालय में भी चल रहा है लेकिन कुछ दिनों से रमेश चौरडीया अपने दबंगई और मंत्रालय तक फेकफाक होने का दावा करते हुए सारे कानून के नियमो की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश चौरडिया का दावा हैं की आज तक पुलिस प्रशासन उनका बाल बांका नहीं कर पाया हैं अब देखना यह हे की पुलिस अधीक्षक द्वार क्या करवाही की जायेगी।

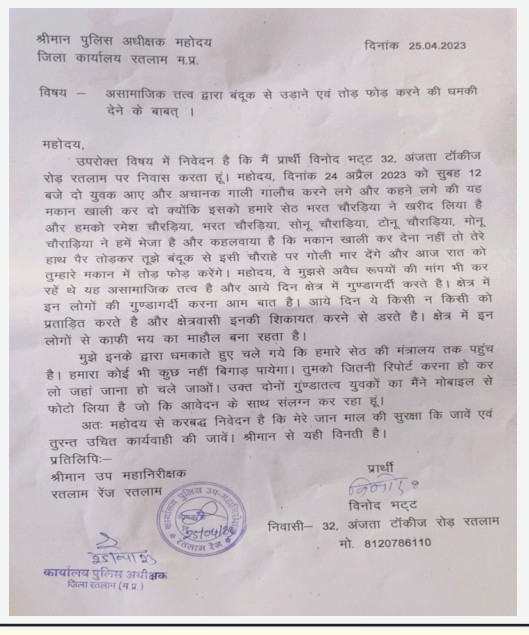

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला कार्यालय रतलाम म.प्र.

दिनांक 25.04.2023

विषय — असामाजिक तत्व द्वारा बंदूक से उड़ाने एवं तोड़ फोड़ करने की धमकी देने के बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी विनोद भट्ट 32, अंजता टॉकीज रोड़ रतलाम पर निवास करता हूं। महोदय, दिनांक 24 अप्रैल 2023 को सुबह 12 बजे दो युवक आए और अचानक गाली गालौच करने लगे और कहने लगे की यह मकान खाली कर दो क्योंकि इसको हमारे सेठ भरत चौरड़िया ने खरीद लिया है और हमको रमेश चौरड़िया, भरत चौरड़िया, सोनू चौराड़िया, टोनू चौराड़िया, मोनू चौराड़िया ने हमें भेजा है और कहलवाया है कि मकान खाली कर देना नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तूझे बंदूक से इसी चौराहे पर गोली मार देंगे और आज रात को तुम्हारे मकान में तोड़ फोड़ करेंगे। महोदय, वे मुझसे अवैध रूपयों की मांग भी कर रहें थे यह असामाजिक तत्व है और आये दिन क्षेत्र में गुण्डागर्दी करते है। क्षेत्र में इन लोगों की गुण्डागर्दी करना आम बात है। आये दिन ये किसी न किसी को प्रताड़ित करते है और क्षेत्रवासी इनकी शिकायत करने से डरते है। क्षेत्र में इन लोगों से काफी भय का माहौल बना रहता है।

मुझे इनके द्वारा धमकाते हुए चले गये कि हमारे सेठ की मंत्रालय तक पहुंच है। हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। तुमको जितनी रिपोर्ट करना हो कर लो जहां जाना हो चले जाओं। उक्त दोनों गुंण्डातत्व युवकों का मैंने मोबाइल से फोटो लिया है जो कि आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं।

अतः महोदय से करबद्ध निवेदन है कि मेरे जान माल की सुरक्षा कि जावें एवं तुरन्त उचित कार्यवाही की जावें। श्रीमान से यही विनती है।

प्रतिलिपिः—
श्रीमान उप महानिरीक्षक
रतलाम रेंज रतलाम

प्रार्थी
विनोद भट्ट
निवासी— 32, अंजता टॉकीज रोड़ रतलाम
मो. 8120786110

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला रतलाम (म.प्र.)

जनपद प्रतिनिधि रविंद्र कृष्णचंद्र ठाकूर (सिसोदिया) ने ग्रामों में पेयजल और अन्य योजनाओं के लिए रखे प्रस्ताव

रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले की आलोट जनपद की बैठक आयोजित की गई।जिसमे आलोट सी ई ओ व अधिकारियों और जनपद सदस्यों के समक्ष बैठक संपन्न हुई।जिसमे जनपद प्रतिनिधि रविंद्र कृष्णचंद्र ठाकूर (सिसोदिया)ने अपनी पंचायतों में पानी की व्यवस्था, व सरकार की अन्य योजनाओं को गांवो में लागू करवाने के लिए अधिकारियों को अवगत करवाया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023